माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2025–2026 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

"न गिराया किसी को कभी, न खुद को उछाला,
कटा जिंदगी का सफ़र धीरे–धीरे।
जहां आप पहुँचे छलांग लगा–लगा कर,
मैं भी पहुँचा वहीं मगर धीरे–धीरे।"

1. यह हमारी सरकार का तीसरा बजट है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उनके जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया है।

2. अध्यक्ष महोदय, 11 दिसम्बर, 2022 को कांग्रेस सरकार को सत्ता की बागडोर सम्भालते ही नाजुक वित्तीय स्थिति, पनपते Mining Mafia, पूर्व सरकार द्वारा लापरवाही से की गई भरपूर फिजूलखर्ची जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछली सरकार द्वारा कई सरकारी भवनों तथा अन्य पूंजीगत कार्यों का बिना बजटीय प्रावधानों के ही निर्माण किया गया और बिना ज़रूरत के संस्थानों को खोला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश भर में Civil Contractors के प्रति करोड़ों रुपये की देनदारियां खड़ी हो गईं। एक हज़ार करोड़ रूपये से ज्यादा राशि के अधिकाँश भवन बिना किसी विवेक के बनाए गए जो कि आज तक किसी भी काम में नहीं लाए जा सके हैं। इनके निर्माण के लिए Centrally Sponsored Schemes तथा Externally Aided Projects के अन्तर्गत मिलने वाली राशि का दुरूपयोग किया गया जिसके परिणाम कई प्रकार की चुनौतियों के रूप में वर्तमान सरकार के सामने आए।

3. आने वाला काल गम्भीर संकट व Transition का हैः वैश्विक व्यापार युद्ध, टैरिफ वार, गिरती हुई

अर्थव्यवस्थाएँ, बदलते मूल्य, उभरती हुई नई Geo Political व सामरिक चुनौतियाँ तथा उनका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव। देश व प्रदेश दोनों इससे अछूते नहीं हैं। देश के मार्केट व देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। मुझे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त करनी आवश्यक लगती है। उद्योगों की वृद्धि दर धीमी हो रही है, व्यापार पर असर पड़ा है, रोज़गार के अवसर भी घट रहे है और निजी खपत में कमी के कारण घरेलू मांग में भी कमी आ रही है। FIIs (Foreign Institutional Investors) की भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली से आ रही गिरावट से Retail Investors का लाखों–करोड़ों का नुकसान हो गया है। RBI को भी मुद्रास्फीति और कमजोर रुपये के चलते नीतिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। कुछ के लिए यह केवल अस्थायी ठहराव है जबकि मैं इसे दीर्घकालीन चुनौती के रूप में देख रहा हूँ।

4. इन सब चुनौतियों के बीच हमारा प्रदेश और भी अधिक प्रभावित हुआ है। एक ओर जो हमें देय है वह मिल नहीं रहा–जैसे PDNA, BBMB का शेयर। NPS शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों का लगभग 9 हज़ार करोड़ का फण्ड केन्द्र(NSDL) से लेना शेष है। GST Compensation पहले ही बंद है और दूसरी ओर अब Revenue Deficit Grant (RDG) की टेपरिंग से साल दर साल की गिरावट जारी है।

5. VAT के स्थान पर GST लागू करके व GST Compensation देने के बाद भी राज्य सरकार को वर्ष 2023–2024 तक कुल 9 हज़ार 478 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। RDG के मामले में भी ऐसा ही हुआ है और मेरी नज़र में RDG कोई ग्रान्ट नहीं है। RDG एक प्रकार का Post Devolution Compensation है, उन प्रदेशों के लिए जो मूलतः Revenue Deficit इकाईयाँ हैं तथा जिनका गठन किसी आर्थिक स्वायत्तता या आत्म

निर्भरता के आधार पर नहीं अपितु इन क्षेत्रों की जन–आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्य इसीलिए Special Category के राज्य माने गए।

6. योजना आयोग के बन्द होने व पिछले 10 सालों में भारत सरकार द्वारा हर योजना व वित्तीय सहायता में तरह–तरह की शर्तें लगातार लगाए जाने के कारण हम आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होते जा रहे हैं। सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण 2021–2022 से 2025–2026 के दौरान RDG पिछले पाँच वर्षों में तेजी से गिरी है।

7. चौदहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर पाँच वर्षों 2015–16 से 2019–20 के लिए RDG के रूप में हमें 40 हज़ार 624 करोड़ रूपये मिले अर्थात इन पाँच वर्षों में हर वर्ष में हमें लगभग 8 हज़ार करोड़ रूपये की RDG मिली। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में प्रदेश को मिलने वाली RDG 40 हज़ार 624 करोड़ रूपये से घटकर 37 हज़ार 199 करोड़ रूपये हो गई, जोकि यदि मुद्रास्फिति को ध्यान में रखें तो यह आज 30 हज़ार करोड़ रूपये के आस–पास बनती है। सदन को इस बात का भी आश्चर्य होगा कि 15वें वित्त आयोग में कुछ ऐसे कारणों से जो बिलकुल तर्कसंगत नहीं हैं, 2021–22 से 2025–26 तक लगातार हर वर्ष RDG कम की गई।

8. 2021–22 में यह Grant 10 हज़ार 949 करोड़ रूपये थी, 2022–23 में ये घटकर 9 हज़ार 377 करोड़ रूपये हो गई जबकि 2023–24 में यह फिर गिरी और 8 हज़ार 58 करोड़ रूपये रह गई। इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 2024–2025 में RDG घटकर 6 हज़ार 258 करोड़ रूपये हो गई और अब आने वाले साल 2025–26 में यह मात्र 3 हज़ार 257 करोड़ रूपये है। 10 हज़ार 249 करोड़ रूपये से 3 हज़ार

257 करोड़ रूपये तक RDG का गिरना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना अधिक प्रभावित करेगा आप भली–भान्ति समझ सकते हैं।

9. 2025–2026 का साल हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी नज़र में पिछले कई दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण साल है। लेकिन मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम इस चुनौती को प्रदेश की जनता, कर्मचारी वर्ग तथा सदन के साथ मिलकर स्वीकार करेंगे और भारत सरकार के समक्ष प्रदेश के साथ अन्याय न हो इस सम्बन्ध में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे।

10. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में मानसून के दौरान राज्य को भारी तबाही का सामना करना पड़ा जोकि राज्य के इतिहास की एक सबसे बड़ी तबाही थी, जिसमें हजारों घर तबाह हुए तथा बहुमूल्य जाने गई। हमने अपने संसाधनों से 4 हज़ार 500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज़ दिया। हम केन्द्र का धन्यवाद करते हैं, जिन्होने Central PDNA टीम भेजी और प्रदेश के अधिकारियों के साथ मिलकर इसका आंकलन किया और 9 हज़ार 42 करोड़ रूपये की PDNA Report केन्द्र को नवम्बर, 2023 में भेजी गई। अगस्त 2024 में PDNA के मानक अधिसूचित होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से नवम्बर 2024 से फरवरी 2025 के बीच धन की मांग बारे सम्पर्क बनाए रखा परन्तु फिर भी अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। आशा है कि केन्द सरकार प्रदेश के हित में यह राशि शीघ्र ही जारी करेगी।

11. हमारी सरकार ने सभी चुनौतियों के चलते हिमाचल प्रदेश को आत्म–निर्भर बनाने का संकल्प लिया। जहाँ आवश्यकता थी, वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। कुछ बदलावों का भरपूर विरोध भी हुआ तथा विपक्ष द्वारा तंज़ भी कसे गए। इन सब की परवाह न करते हुए हमारी सरकार प्रदेश के विकास के संकल्प को साकार करने के पथ पर

अडिग रही और व्यवस्था परिवर्तन के सफ़र को जारी रखा गया। गत दो वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकार द्वारा किए कार्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्यों को न तो रूकने देंगे, न ही उनमें कोई कमी आने देंगे बल्कि हमने जो प्रयास किए हैं उनके कारण विकास के कार्यों में अभूतपूर्व तेज़ी देखी गई है। हमने न सिर्फ टेण्डर की प्रक्रिया को सरल किया है बल्कि लगातार मूल्यांकन के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं को निश्चित समय सीमा में धरातल पर उतारने की पहल की है। पिछले दो वर्षों में लिए गए निर्णयों के सुखद परिणाम आज सामने आने शुरु हो गए हैं।

12. पिछली सरकारों द्वारा Resource Mobilization की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिससे राज्य की कर्ज पर निर्भरता बढ़ी है। परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में विशेष कदम उठाए गए हैं, हमारे प्रयासों के परिणाम प्रथम वित्त वर्ष (2023–24) में ही आने शुरू हो गए थे । राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की दर जो कि वर्ष 2022–23 में 6.89 प्रतिशत थी वर्ष 2023–24 में बढ़कर 7.03 प्रतिशत हो गई। राज्य के अपने राजस्व प्राप्ति का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा वर्ष 2022–23 में 35.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 37.92 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार से राज्य के अपने राजस्व और कुल खर्चे की दर जो कि वर्ष 2022–23 में 24.99 प्रतिशत थी वर्ष 2023–24 में बढ़कर 27.54 प्रतिशत हो गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में विभिन्न मदों की आय में संतोषजनक वृद्धि दर्ज हुई है। विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर VAT में 27.98 प्रतिशत, State Excise में 21.48 प्रतिशत, बिजली में 16.74 प्रतिशत, Non & Ferrous Mining and Metallurgical Industries 15.85 प्रतिशत, Taxes on Vehicles में 15.78 प्रतिशत व स्टाम्प तथा Stamps and Registration Fees में 10.44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा बिजली के उपयोग पर दी जाने वाली Subsidy का भी

युक्तिकरण किया गया है, जिसके तहत साधन सम्पन्न लोगों द्वारा स्वेच्छा से Subsidy को छोड़ा जा रहा है और साथ ही इससे सरकार के संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023–2024 में State Excise Duty और VAT में 867 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2024–2025 के संशोधित अनुमानों के अनुसार लगभग 300 करोड़ रूपये की वृद्धि होने की सम्भावना है। यह वृद्धि हमारी सरकार द्वारा Excise Policy में किए गए बदलावों के कारण ही सम्भव हो पाई है। राज्य की आत्मनिर्भरता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

13. हमारी सरकार ने उपकर के माध्यम से भी आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप, वर्ष 2023–24 में शराब पर लगाए गए उपकर से 145 करोड़ रूपये अर्जित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शराब पर लगाए गए उपकर को छोडकर वर्ष 2024–25 से वर्ष 2025–26 के दौरान विभिन्न उपकरों से 126 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय अनुमानित है।

14. हम सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि Resource Mobilization बढ़ाई जा सके। मुझे इस सदन के पक्ष एवं विपक्ष, सभी सदस्यों से यह आग्रह करना है कि वे मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव दें।

15. अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में पहली बार राज्य द्वारा लिए जा रहे Loans व इनकी Repayment की वास्तविकता से लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ क्योंकि इस पर चर्चा करना जरूरी लगता है। महोदय, सरकारें आती है, जाती है, परन्तु मुझे यह कहना है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए बाध्य है, जो राज्य सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (FRBM) के अनुसार 2024–25 और 2025–26 के लिए क्रमशः 3.5 और 3 प्रतिशत

है। राज्य सरकार तब तक धन उधार नहीं ले सकती जब तक कि उसे भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत अधिकृत नहीं किया गया हो। 2024–25 के लिए राज्य का सामान्य उधार लेना भारत सरकार द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है और इसे 6 हज़ार 551 करोड़ रुपये पर Cap किया गया है। इसी तरह भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शुद्ध ऋण सीमा की गणना करेगी और उचित समय पर राज्य सरकार को सूचित करेगी। किसी भी वर्ष में उधारी सीमा का अधिक उपयोग होने की स्थिति में, इसे केन्द्र सरकार द्वारा अगले वर्ष की सीमा से काट दिया जाता है। यहां मै यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार किसी भी Source से कोई भी ऋण केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं ले सकती। इसलिए राज्य सरकार के पास निर्धारित ऋण सीमा से परे जाने का कोई विकल्प नहीं है। जब वर्तमान सरकार सता में आई तो 31 मार्च, 2023 को पिछली सरकार से 76 हज़ार 185 करोड़ रूपये के ऋण विरासत में मिले जिसका भुगतान और ब्याज की वापसी हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। हमें पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर 12 हज़ार 266 करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान तथा 8 हज़ार 87 करोड़ रूपये की ऋण वापसी करनी पड़ी। इस तरह से हमारी सरकार के पास 29 हजार 46 करोड़ रूपये के लोन में से मात्र 8 हज़ार 693 करोड़ रूपये ही विकास कार्यों के लिए बचे। स्पष्ट है कि हमने जो लोन लिया उसका 70 प्रतिशत पुराने लोन का मूलधन और ब्याज लौटाने में चला गया।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

16. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के विकास के आंकड़े प्रस्तुत करता हूँः–

- 2024–25 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4 प्रतिशत् की दर से बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 3.8 प्रतिशत् की वृद्धि दर अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024–25

के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय दो लाख 1 सौ 62 रूपये अनुमानित है।

- अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को मापने का प्रमुख सूचक है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत् रहने का अनुमान है। 2024–25 के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2 लाख 57 हज़ार 212 रुपये रहने का अनुमान है, जोकि देश की प्रति व्यक्ति आय से 57 हज़ार 50 रूपये अधिक है। 2024–25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 32 हज़ार 185 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

प्रदेश अर्थव्यवस्था

17. मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश को "**Natural**" तथा "**Green**" प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। माननीय सदन के सभी सदस्यों का ध्यान में "**Natural**" तथा "**Green**" इन दो शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

18. "**Natural**" शब्द एक ओर हमारे प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता को रेखांकित करता है वहीं दूसरी ओर यह विकास तथा पर्यावरण के प्रति मेरी सरकार के दृष्टिकोण को भी इन्गित करता है। चाहे कृषि विभाग हो या बागवानी, चाहे पशुपालन हो या वन विभाग, चाहे उद्योग हो या परिवहन, हमारा यही प्रयास है कि हमारे विकास का दर्शन व उसके मूल्य Natural/ प्राकृतिक हों। हम Chemicals, Fertilizers, Pesticides तथा अन्य प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं के प्रयोग को कम करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी हम पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं।

19. मैं अक्सर यह कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश **Lungs of North India** है। हम अपने वनों की रक्षा करते हैं, Ecology व पर्यावरण का संतुलन रखते हैं। ये सब

एक तरह से हमारी Ecological Services हैं जिन्हें हम मिट्टी, पानी, शुद्ध वायु, अच्छी जलवायु के रूप में देश को देते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की Ecological Services के देश के पर्यावरण में योगदान को देखूं तो एक अनुमान के अनुसार वह प्रतिवर्ष लगभग 90 हज़ार करोड़ रूपये बनेगा। सरकार इसका एक तकनीकी व वैज्ञानिक मूल्यांकन शीघ्र करवा रही है। दुःख है तो इस बात का कि अभी तक हमारी इस Opportunity Cost की कोई भरपाई नहीं हो पाई है। इसी लिए मेरी सरकार यह प्रयास कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के इस बहुमूल्य योगदान को हम भारत सरकार व 16वें वित्तायोग के समक्ष दृढ़ता से रखें।

20. कृषि बागवानी तथा अन्य विभागों के बारे में जब आगे उल्लेख आएगा तो प्राकृतिक/Natural दिशा में किए प्रयास आपके समक्ष और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे।

21. अब मैं **Green Himachal** के विषय में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 17 मार्च 2023 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत अपने पहले बजट में मैंने कहा था कि हमारी सरकार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को **Green Energy State** के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

22. मैं दो–तीन बातों से **"Green Energy State"** वाले **Concept** को स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए अगर हम प्रदेश की ऊर्जा की सारी खपत के लिए, जो लगभग 14 हज़ार मिलियन यूनिट है, का लगभग 90 प्रतिशत **Renewable/Green Energy** स्रोतों का प्रयोग करें तो हम एक "ग्रीन स्टेट" कहला पाएंगे। इसका सीधा लाभ प्रदेश में हो रहे औद्योगिक व कृषि के उत्पादन को मिलेगा। हम इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। धीरे–धीरे हमारी ऊर्जा खपत अब मूलतः **Hydro** व **Solar** स्त्रोतों पर आधारित हो गई है। प्रदेश में हमारी सरकार के इस कार्यकाल में सौर ऊर्जा में जितनी

वृद्धि हुई है वह अतुलनीय है – इतनी कभी नहीं हुई। इस बारे में विस्तृत उल्लेख आगे होगा।

23. Green State का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है परिवहन (**Transport**) का क्षेत्र। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि **Green House Gases** के **Emission** जिससे जलवायु पर दुष्प्रभाव पड़ता है, का लगभग 16 से 20 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र से आता है। अगर हमें **Natural** व **Green** हिमाचल की ओर बढ़ना है तो आवश्यक है कि हम परिवहन के क्षेत्र में **e-Vehicles** व उसके लिए **Enabling Infrastructure** पर बल दें।

24. चरण बद्ध रूप से हम **HRTC** के **Fleet** में **e-buses** को बढ़ावा दे रहे हैं। चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्गों पर जैसा मैंने सदन में वायदा किया था कि चार्जिंग स्टेशन तथा **Infrastructure** बनाया जाएगा जोकि बनाया गया है और बनाया भी जा रहा है। सरकारी विभागों में भी ई-गाड़ियों का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। टैक्सियों के लिए भी विशेष अनुदान दिया जाएगा ताकि प्रदेश में ई–वाहनों का प्रयोग बढ़े। इसकी चर्चा मैं बजट भाषण में आगे भी करूंगा।

25. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। सरकार ग्रामीण आजीविका को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही है। मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करना चाहूँगाः–

- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक गेहूँ और मक्की के लिए Minimum Support Price की घोषणा की गई है।
- सेब, आम और अन्य फलों की खेती को बढ़ावा देने, उच्च मूल्यों वाले फूलों की संरक्षित खेती करने व मौसम आधारित फसल बीमा योजना

इत्यादि के माध्यम से किसानों/बागवानों को लाभ दिया जा रहा है।

- हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जाए।

26. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए Products की बिक्री के लिए एक ई–कॉमर्स वैबसाईट "himira.co.in" का आरम्भ किया गया। अन्य उत्पादों के साथ–साथ प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की का आटा इस प्लेटफॉर्म पर "हिम भोग'' Brand के नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। Natual Farming कर रहे एक लाख 58 हज़ार 785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। आने वाले समय में हमारी सरकार द्वारा बाजार को ग्रामीण उद्यमियों (Entrepreneurs) के द्वार पर लाने के प्रयास को और भी प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जाएगा।

27. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश में 8 पैन्शन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। **"इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना"** के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। **"स्वर्ण जयंती आश्रय योजना"** में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मेरी सरकार की Flagship Scheme **"मुख्यमन्त्री सुख आश्रय योजना''** के अन्तर्गत सरकार की ओर से शिमला जिला से 22 Children of the State के पहले दल को 13 दिनों के शैक्षणिक भ्रमण (Educational Tour) पर देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया। तदोपरान्त बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी तथा सिरमौर जिलों से भी कुल ऐसे 77 बच्चों को देश के विभिन्न भागों में शैक्षणिक

भ्रमण के लिए ले जाया गया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आगामी वित्त वर्ष में भी अन्य जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही, उनकी उच्च शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग के लिए **"मुख्यमंत्री सुख–आश्रय कोष"** की स्थापना की गई है, जिसमें स्वैच्छिक योगदान और CSR फण्ड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग चार हज़ार से अधिक बच्चों को प्रमुख भारतीय त्यौहारों के लिए त्यौहार भत्ता एवं अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, वस्त्र भत्ता, पोषण अनुदान, मिश्रित अनुदान, उच्च शिक्षा और कौशल विकास, स्टार्ट–अप अनुदान के रूप में 14 करोड़ 77 लाख 02 हज़ार का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर और हमीरपुर में 2 Children of the State को भूमि आवंटित की गई व निर्माण हेतु राशि भी प्रदान की गई।

28. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैने पहले भी कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश को **Natural, Green State, Lungs of the North India** के रूप में देखता हूँ और यदि मैं इसे पर्यटन से जोड़ूँ तो यहां देश–विदेश से पर्यटक साफ वातावरण और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं। इसी के चलते हमारी सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बजट में वेलनेस सेंटर, आइस स्केटिंग रिंक, और राफ्टिंग सेंटर जैसी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। साथ ही, होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए Interest Subvention Scheme लाई जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हेलीपैड बनाने की योजनाओं के साथ–साथ कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। जिससे यहां बड़े विमानों की Landing सम्भव हो सकेगी और पर्यटकों को आसान और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन (Tea Tourism) और प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की

दृष्टि से विकसित करने पर कार्य कर रही है। हमें विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगें तथा राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

पशुपालन

29. महोदय, हमारी सरकार पशु पालन के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कर रही है। वर्ष 2025–2026 में पशु चिकित्सा, प्रजनन, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, विस्तार सुविधाओं इत्यादि के अतिरिक्त कई नए पग उठाए जाने का प्रस्ताव है।

30. सरकार द्वारा जिला सोलन के दाड़लाघाट में 4 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से बन रहा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील कर दिया जाएगा।

31. भेड़ और बकरी पालकों के कल्याण के लिए एक विस्तृत एवं प्रभावी कार्य योजना लागू की जाएगी। घुमन्तू भेड़ बकरी पालकों के Migratory Routes को Map करके GPS से Track किया जाएगा।

32. Wool Federation के माध्यम से ऊन के सही रख–रखाव हेतु 450 वर्ग मीटर आकार के स्टोर का निर्माण वूल ग्रेडिंग–कम–मार्केटिंग सेंटर बनूरी, पालमपुर में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में भेड़ की ऊन की निर्बाध खरीद हेतु 50 लाख रूपये के Revolving Fund का प्रावधान किया जाएगा।

33. मैं प्रदेश की पंजीकृत दूध Societies के सुदृढ़ीकरण के लिए इन्हें मिलने वाली Freight Subsidy को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर की घोषणा करता हूँ।

34. Milkfed में दूध Procurement के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। Technology की मदद से किसानों को मिलने वाली सभी जानकारी मोबाईल पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए Milkfed में ERP System को लागू किया जाएगा। साथ ही सभी

पशुओं को भी Life Cycle Approach के अन्तर्गत एक Integrated Digital Platform पर लाया जाएगा।

35. वित्तीय वर्ष 2025–2026 में डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर और सोलन ज़िलों के लिए लगभग 10 करोड़ 73 लाख 27 हज़ार रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों में Milk Processing Plant डगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, दुग्ध उत्पादकों और तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण, और दूध खरीद इकाइयों का डिजिटलीकरण शामिल है।

36. राज्य में डेयरी गतिविधियों के सुधार हेतु नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहडू में 20 हज़ार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयन्त्र और 2 Milk Chilling Centre (MCC) ऊना और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगें।

37. मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रूपये प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान या कोई Society 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से Transport Subsidy भी दी जाएगी। इस प्रकार बेचे गए दूध में किसान को आठ रूपये प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे।

पशुपालन के क्षेत्र में कुल 673 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

कृषि

38. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। बेहतर प्रबन्धन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही आठ योजनाओं को **मुख्यमन्त्री कृषि संवर्धन योजना** एवं **मुख्यमन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना** के रूप में एकीकृत किया गया है। 2025–2026 के

दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 35 करोड़ रूपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

39. प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तम्भ, किसानों के हित में सरकार "**Agriculture Loan Interest Subvention Scheme**" लाएगी। जिसके तहत ऐसे किसानों जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रूपये कृषि लोन को चुकाने हेतु, सरकार बैंको के माध्यम से One Time Settlement Policy लाएगी। इस Policy के अन्तर्गत मूल धन पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

40. 2025–2026 के दौरान एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही Certification के लिए नए किसानों को "Certified Evaluation Tool For Agriculture Resource Analysis" (CETARA Portal) पोर्टल पर Register किया जाएगा।

41. मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 से बढ़ाकर 40 तथा गेहूँ को 40 से बढ़ाकर 60 रूपये प्रति किलो करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर स्वयं ले कर आते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से Freight Subsidy भी दी जाएगी। किसानों को बेहतर Marketing के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु e-Commerce Platforms, NCDC (National Cooperative Development Corporation) से भी जोड़ा जाएगा।

42. विश्व में 78 प्रतिशत् हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने High Curcumin Content के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश के पास **प्राकृतिक हल्दी** के रूप में उत्पादन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। इस सन्दर्भ मैं निम्न दो घोषणाएं करता हूँः–

- जिला हमीरपुर में स्पाईस पार्क (Spice Park) का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश मे उगाए जा रहे मसालों की Value addition होगी व बाजार में एक नई पहचान मिलेगी।

- आगामी वित्त वर्ष से प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 90 रूपये प्रति किलो करने की घोषणा करता हूँ।

43. 2025–2026 के दौरान कृषि विभाग के सभी Government Farms (सरकारी खेतों) को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा और किसानों को इन Farms का और अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए जाएंगें :–

- 15–20 प्रतिशत हिस्से में पारम्पारिक फसलों (हल्दी, अदरक, अरबी, कटहल, रतालू आदि) की खेती की जाएगी और विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगें।

- ICAR–CPRI द्वारा विकसित SoP के तहत खरीफ़ 2025 से आलू के बीज का उत्पादन आठ Potato Development Stations में फिर से शुरू किया जाएगा।

44. प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वर्षो से आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। राज्य में कुल सब्जी उत्पादन में आलू का 20 प्रतिशत हिस्सा है। अतः आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ऊना

जिले में लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत से 500 KG Per Hour की क्षमता वाले Potato Processing Plant को स्थापित करने जा रही है। जोकि प्रदेश में वर्ष के दौरान 3 हज़ार 400 हैक्टेयर में उगने वाली आलू की दोनों मौसमों की फसलों के लगभग 54 हज़ार 200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

45. गेहूँ और मक्का के बेहतर भण्डारण के लिए प्रदेश में उच्च तकनीक से चालित Silos स्थापित किये जाएंगे।

46. अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और **"हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना"** इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार इस परियोजना हेतु 154 करोड़ रुपये का व्यय करेगी। परियोजना के तहत निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगेः–

- 100 गाँवों में सिंचाई योजनाओं का निर्माण करके उन्हें Local Committees को Transfer किया जाएगा।
- कृषि यन्त्रीकरण पर सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएगें।
- परियोजना क्षेत्र के लाभार्थी किसानों के लिए 1 हज़ार 500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे व लगभग 4 हज़ार Demonstrations on Vegetable Cultivation आयोजित की जाएंगी।
- Millets के प्रचार–प्रसार के साथ खाद्यान्न उत्पादकता पर लगभग 2 हज़ार 400 Demonstrations आयोजित की जाएंगी।
- **"मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना"** को आगे बढ़ाते हुए अब किसानों को जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा हेतु Solar Fencing, जाली दार और कान्टेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान की जाएगी।

बागवानी

47. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बागवानी न केवल किसानों/बागवानों के लिए आजीविका का स्रोत है बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता का प्रमुख स्तम्भ है। हमारी सरकार ने बागवानो की समस्याओं को समझते हुए Universal Carton का इस्तेमाल आरम्भ किया और MIS के अंतर्गत लगभग 153 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाई। मैं 2025–2026 के लिए इस क्षेत्र में निम्न घोषणाएं करता हूँ :–

- 4 हज़ार हैक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए Topographic Survey किया जाएगा।
- प्रदेश में किसान उद्यम नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाएगा जोकि बागवानी उत्पाद की Marketing, Processing, आदि में सहायक होगा।
- 114 Lift Irrigation Schemes वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी की जाएगी।
- HPSHIVA परियोजना के तहत वर्ष 2025–2026 में 100 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।

48. पूर्व की सरकारों ने बागवानी के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्यौगिकी को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण इस क्षेत्र में डिजिटल क्रान्ति नही आ सकी। अतः वर्तमान सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ डिजिटल एग्रीटैक सेवाएं सृजित की जाएगी। जिसमें बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार, विपणन के लिए डिजिटल प्लैट फार्म और कृषि आय को बढ़ाने के लिए प्रौद्यौगिकी और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

49. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Weather Based Crop Insurance Scheme के अन्तर्गत 60 हजार से अधिक बागवानों को लाभान्वित करने के साथ–साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना में

अब तीन और फसलों लीची, अनार तथा अमरूद को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत सेब के लिए 36, आम के लिए 56, प्लम के 29, आड़ू के लिए 16, नीम्बू के लिए 58, आनार के लिए 21, लीची के लिए 38 और अमरूद के लिए 22 ब्लॉकों को लाया जाएगा। यह कदम कृषि क्षेत्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और साथ ही यह किसानों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

50. राज्य में Sub tropical बागवानी को बढ़ावा देने के लिए Sub Tropical फलों को High Density Plantation के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके साथ ही 48 सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे लगभग 5 हज़ार किसान परिवार लाभान्वित होंगें। इसके लिए 200 करोड़ रूपये व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन

51. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 20 हज़ार से अधिक मछुआरे, मत्स्य कृषक तथा अन्य कारोबारी मछली पालन व्यवसाय से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत भाईयों व बहनों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से में निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- वर्तमान में प्रदेश सरकार जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों से 15 प्रतिशत दर से Royalty लेती है। मैं इस Royalty की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ। इससे इन्हें लगभग 75 लाख रूपये का लाभ होगा।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 20 हैक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण किया जाएगा।
- 120 नई ट्राऊट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

- पतलीकूहल में एक ट्राऊट फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा।
- राज्य के मछुआरों को Fish Transportation हेतु तिपहिया वाहन व मोटर साईकल वितरित किए जाएंगे।
- मछुआरों की पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

52. इसके अतिरिक्त 10 Biofloc Culture Units, 3 Trout Hatcheries, 4 Fish Feed Mills, 2 Ice Plants, 5 Biofloc Fish Ponds और 2 Ornamental Fish Farming Units का निर्माण किया जाएगा।

वन विभाग

53. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व **Green Himachal** के सपने को साकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के विस्तारीकण के विभिन्न कार्यक्रमों को नया रूप दिया गया है। 2025–2026 के लिए 5 हज़ार हैक्टेयर का वृक्षारोपण लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें जंगली फलों के पौधों और अन्य फलदार पेड़ों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार ने यह पहल की है, इससे न सिर्फ वन क्षेत्र में जैव विविधता आएगी बल्कि बन्दर व अन्य जीवों को आबादी में आने से रोका जा सकेगा।

54. वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मैं "**राजीव गाँधी वन संवर्द्धन योजना**", लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना में युवक मण्डलों, महिला मण्डलों तथा स्वयं सहायता समूहों को बंजर भूमि पर वृक्ष, फलदार एवं अन्य उपयोगी पौधों के वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्हें एक हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक के पौधारोपण क्षेत्र प्रबन्धन के लिए दिए जाएंगे। औसत रोपण क्षेत्र 2 हैक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है। 2 हैक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष में इन समूहों को 2 लाख चालीस हजार रूपये फलदार और अन्य वृक्षों को

लगाने व सम्बन्धित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगें। इसके बाद भी पांच साल तक Survival प्रतिशतता 50 प्रतिशत या अधिक होने पर दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ष तक सालाना 1 लाख रूपये तथा 50 प्रतिशत से कम होने पर Proportionately प्रोत्साहन तथा संरक्षण राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल 6 लाख 40 हज़ार की राशि प्रत्येक समूह को मिल सकेगी। इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इन सभी वन क्षेत्रों को Geo Tag किया जाएगा और online monitoring की जाएगी। **इस योजना के लिए 100 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है।**

55. Corporate Social Responsibility(CSR) के अन्तर्गत एक नई Adoption योजना लाई जा रही है। जिसमें बंजर भूमि पर वृक्ष लगाए जाएंगे। इस प्रयास से न केवल प्रदेश के वनों में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय समुदायों को आजीविका भी सुनिश्चित होगी।

56. World Bank, KFW और JICA की सहायता से चल रही तीन परियोजनाओं के तहत अगले वर्ष के दौरान लगभग 200 करोड़ रूपये व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

57. हिमाचल प्रदेश आक्रामक प्रजातियों जैसे Lantana और Parthenium Grass के प्रसार, चीड़ की सूखी सुईयों और कृषि–अवशेषों से होने वाली जंगल की आग, जैव विविधता की हानि, जल संकट, आवास और पारंपरिक आजीविका के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। भूस्खलन जैसी आपदाएँ स्थानीय समुदायों की आजीविका को अस्थिर कर रही हैं। मेरी सरकार इन समस्याओं को अवसर में बदलने के लिए कचरे को Biochar, Bio-Energy, Bio-Fertilizers, Bio-Pesticides, Green Energy, और Carbon Credits जैसे उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखती है, जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि ग्रामीण

अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित होगी।

58. हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, घने वन, बर्फ से ढके पहाड़, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण Eco-Tourism के लिए एक आदर्श स्थल है। Eco-Tourism स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस से लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार निम्न कदम उठा रही हैः–

- सरकार ने वर्ष 2024 में Eco-Tourism नीति को संशोधित किया है। इस नीति से Eco-Tourism गतिविधियों को गति मिलेगी।

- वर्ष 2024 में 7 Eco-Tourism साइटों के लिए संचालकों (Operators) को चयनित किया गया है। अगले चरण में 78 नई Eco-Tourism साईटों को आबंटित किया जाएगा।

- वन विभाग के विभिन्न सर्कल में Eco-Tourism Societies गठित की गई हैं जो इन गतिविधियों को नियन्त्रित एवं संचालित करेगी।

- विभिन्न Eco-Tourism गतिविधियों के माध्यम से अगले 5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जाएगा।

59. प्रदेश में Forest Clearance के मामलों को अभूतपूर्व तेजी से Process किया है। पिछले दो वर्षों में 208 मामलों में FCA के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। इस पहल से वर्षों से रुके हुए Projects को शुरू किया जा सका है। इसी तरह से Forest Rights Act के तहत भी 560 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है।

60. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत गन्तव्य ही नही अपितु देव भूमि भी है। यहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है। धार्मिक पर्यटन, Adventure Tourism तथा Health Tourism प्रदेश में पर्यटन विकास के मुख्य स्तम्भ है। इस दिशा में हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है।

61. अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा विशेषकर कांगड़ा जिले को अन्तर्राष्ट्रीय Tourist Map पर लाने के लिए पूर्व में घोषित प्रयासों का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। कांगड़ा में गगल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू–अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। भू–अधिग्रहण के पूरा होते ही इसके निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। 2025–2026 के दौरान इसके लिए लगभग 3 हज़ार करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है। मण्डी के बल्ह में प्रस्तावित Airport के सम्बन्ध आगामी कार्रवाई हेतु मामला Airport Authority of India के साथ उठाया जाएगा।

62. अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार New Tourism Destinations को दो चरणों में लगभग 2 हज़ार 400 करोड़ रूपये की लागत से विकसित करेगी। प्रथम चरण में 2025–2026 में निम्न कार्य किए जाएंगेः–

- मनाली, कुल्लू, नग्गर व नादौन में वैलनेस सेन्टर।
- धर्मशाला, शिमला व मण्डी में आईस स्केटिंग रिंकस।
- पालमपुर और नगरोटा बगवां का सौन्दर्यीकरण।
- बाबा बालकनाथ मन्दिर परिसर में पर्यटन सुविधाएं।

- Adventure Tourism को बढ़ावा देने के लिए नादौन में रॉफ्टिंग सेन्टर व प्रदेश के जलाशयों में Water Sports एवं अन्य Adventure Sports की शुरूआत।

63. पर्यटकों को हिमाचल में आकर्षित करने के लिए Home Stay Units की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह Units न केवल महंगे होटलों का एक विकल्प हैं बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को अधिक समय के लिए रूकने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं प्रदेश के युवाओं को राजगार देने के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई योजना **"मुख्यमन्त्री पर्यटन स्टार्ट अप योजना"** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं द्वारा Home Stay Units और Hotel बनाने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत **Interest Subvention** तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत **Interest Subvention** दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राज मार्गों तथा जिला मुख्यालयों पर चलाने के लिए प्रदेश के युवाओं को 30 प्रतिशत उपदान Food Vans उपलब्ध करवाई जाएंगी। योजना के तहत 50 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

64. हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा क्योंकि अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पर्यटन का ढांचागत विकास लगभग अपनी सीमा के अनुसार हो चुका है। हम एक नई योजना के तहत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 3 Star, 4 Star, 5 Star या उससे ऊपर 7 Star तक के होटल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमन्त्रित करेंगे। इन Projects में High End Health and Wellness Centres, Senior Citizen Townships, High Value Tourism Experience Centres और विश्वस्तरीय सुविधा युक्त Tourist Attraction स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस Projects, Hotels और Resorts को स्थापित करने के लिए Complete Application Submit करने पर एक महीने में सारी Permissions दे दी जाएंगी।

65. प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में माता श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 58 करोड़ रूपये की Detailed Project Report स्वीकृत होते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार माता श्री ज्वालाजी मन्दिर के लिए 100 करोड़ रूपये, माता श्री नैना देवी मन्दिर के लिए 100 करोड़ रूपये तथा धर्मशाला के तपोवन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के Convention Centre के निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपये व्यय किए जाएगें। दूसरे चरण में माता श्री ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा, चौरासी मन्दिर भरमौर, श्री त्रिलोकीनाथ मन्दिर लाहौल को सम्मिलित किया जाएगा।

66. मण्डी जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां शिवधाम की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करके जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

67. महोदय, कांगड़ा जिले को **Tourism Desitination** बनाने के मेरी सरकार के लक्ष्य की दिशा में पौंग डैम के साथ–साथ निकटतम क्षेत्रों के विकास हेतु नगरोटा सूरियां, खब्बल व Wellness Centre देहरा की DPR बनाकर भारत सरकार के पर्यटन मन्त्रालय को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के Challenge Based Destination Development हेतु काज़ा और रकछम व छितकुल को पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा। चान्शल को भी पर्यटन स्थल के रूप में Develop किया जाएगा।

68. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप को मालूम है कि हमारी सरकार द्वारा बनखण्डी, कांगड़ा में **Zoological Park** का निर्माण किया जा रहा है और अब हम इसके साथ एक अत्याधुनिक **"Planetarium"** स्थापित करने जा रहे है। यह न केवल स्थानीय निवासियों को स्वःरोज़गार प्रदान करेगा और पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि खगोल विज्ञान और

अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और जागरूकता भी बढ़ाएगा। इसके अलावा, यह बच्चों के लिए एक प्रमुख आकर्षण और शैक्षणिक विकास का केंद्र बनेगा। साथ ही बनखण्डी के क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

69. सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रदेश में चार नए Five Star स्तर के **"Natural Care Wellness Centre"** खोलेगी। ये केन्द्र शान्त प्राकृतिक वातावरण में योग, ध्यान, हर्बल उपचार और पारम्परिक चिकित्सा का अनूठा अनुभव प्रदान करेंगें। साथ ही यहां दिया जाने वाला भोजन व अन्य खाद्य सामग्री भी विशुद्ध रूप से प्राकृतिक होगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश को एक प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना और पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा।

70. सरकार द्वारा रक्कड़, पालमपुर, सुल्तानपुर, जसकोट और शारबो(किन्नौर) में हैलीपोर्टस का निर्माण और संचालन वर्ष 2025–2026 के भीतर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आलू ग्राउंड मनाली, धारकियारी(नाहन), बिलासपुर, बसाल(सोलन) और जनकौर हार(ऊना) के लिए वर्ष 2025–2026 के दौरान Obstacle Limitation Surfaces Survey, DPR जैसी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी।

71. महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त काँगड़ा चाय को GI Tag मिला हुआ है, जोकि प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है। Tea Tourism प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में रोजगार की भी बहुत सम्भावनाएं है। हम वर्तमान कानून में संशोधन करके Tea Tourism को बढ़ावा देने के लिए चाय के बागानों को सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल की तर्ज़ पर Eco-Tourism Destination के रूप में विकसित करेंगे और निवेशकों को बिना किसी समस्या के सभी अनुमतियां प्रदान करेंगे। इससे न केवल Tea Plantation को बढ़ाया और बचाया जा

सकेगा बल्कि हिमाचल की चाय को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी।

ग्रमीण विकास एवं पचायती राज

72. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ग्रमीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं पचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हुए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आजीविका में सुधार लाने एवं आत्मनिर्भर, स्वच्छ और समृद्ध हिमाचल के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं। इसी प्रयास को जारी रखते हुए 2025–2026 के दौरान मैं निम्न कार्यों की घोषणाएं करता हूँ :–

- राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए हम ब्लॉकों का पुनर्गठन करेंगे। यह कदम संसाधनों का बेहतर उपयोग, प्रशासन में कार्यकुशलता लाने और सरकारी सेवाओं को आसानी से आम जनता तक पहुंचाने में कारगर होगा।

- हमारे ग्रामीण संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए Capacity Building अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) के अन्तर्गत 09 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (Extension Training Centres) स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे वे और अधिक प्रभावी ढंग से लोगों की सेवा करने में सक्षम होंगे।

- स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नए स्थानों पर हिम–ईरा शॉप्स, हिमाचली हाट तथा साथ ही Wayside Amenities का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। इससे पारम्परिक हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों को स्थायी मंच मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

मिलेगी। विशेष रूप से Wayside Amenities Scheme के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें और अवसर मिलें। प्रथम चरण में योजना राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे लागू की जाएगी। इसके तहत विश्राम स्थल, फूड कोर्ट, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए Retail Outlets और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित विश्राम स्थल मिलेंगे। यह दूरदर्शी योजना स्थानीय समुदायों और यात्रियों, दोनों के लिए लाभदायक होगी।

- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन दी जाएंगी, जो न केवल भोजन उपलब्ध कराएंगी, बल्कि इन समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री का भी माध्यम बनेंगी।

- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए इन संस्थानों को उनकी सम्पत्तियों के बेहतर Lease Management के माध्यम से आय बढ़ाने के विशेष प्रयास करेंगे। पानी की योजनाओं का प्रबन्धन पंचायत स्तर पर देगें ताकि वे अपनी आय में बढ़ोहतरी कर सकें। इससे सरकारी अनुदानों पर उनकी निर्भरता में कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

- वन विभाग के सहयोग से मनरेगा के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए एक Standard Operating Procedure (SoP) लागू किया जाएगा, जिससे पौधारोपण योजनाओं को प्रभावी और सुनियोजित बनाया जाएगा। यह पहल न केवल प्रदेश के Green Cover को बढ़ाएगी बल्कि पशुधन

के लिए चारे की स्थायी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

73. मैंने पिछले वर्ष के बजट में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 60 रूपये बढ़ाई थी जोकि अप्रत्याशित थी और समतुल्य राज्यों में सबसे अधिक कही जा सकती है। मै घोषणा करता हूँ कि मनरेगा मजदूरों के उत्थान के लिए एवं उन्हे उचित सुविधा देने के लिए एक व्यापक योजना अगले वित्त वर्ष से लागू की जाएगी और इसके अलावा मैं मनरेगा मजदूरी को 20 रूपये बढ़ाकर 320 रूपये करता हूँ।

74. National Rural Livelihoods Mission (NRLM) के अन्तर्गत 2025–2026 में 4 हज़ार योग्य अभ्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन में से 70 प्रतिशत को सुनिश्चित रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

75. 2025–2026 हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में विकास कार्य हेतु 452 करोड़ रूपये तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

76. मैं, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- अध्यक्ष, जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 19,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, जिला परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- अध्यक्ष, पंचायत समिति को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 12,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, पंचायत समिति को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- प्रधान, ग्राम पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, ग्राम पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

श्रम एवं रोजगार

77. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार विभाग के माध्यम से वर्ष 2025–2026 के लिए 50 Campus Interviews को आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा **राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट–अप योजना** के तहत पात्र आवेदकों को ई–टैक्सी खरीदने हेतु 2 करोड़ 91 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। सरकार वित्त वर्ष 2025–2026 में भी विभिन्न सरकारी विभागों एवं निकायों से प्राप्त ई–टैक्सी की मांग अनुसार पात्र आवेदकों को इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान करना जारी रखेगी। इस योजना को और विकसित करते हुए तथा **Natural and Green Himachal** के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मै निम्न घोषणाएं करता हूँ :–

- तीन हज़ार डीजल/पैट्रोल वाले Taxi वाहनों को इलैक्ट्रिक Taxi (e-Vehicles) में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। सरकार प्रदेश के Taxi

तथा ऑटो रिक्शा मालिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन वाहनों को e-Vehicles/e-rickshaw में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत तक की Subsidy देगी।

- सरकार राज्य के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए एक हज़ार बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित करेगी। सरकार इन रूटों हेतु बस अथवा टैम्पों ट्रैवलर की खरीद पर e-Vehicles के लिए 40 प्रतिशत व डीजल/पैट्रोल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर 30 प्रतिशत तक की Subsidy/ Viability Gap Funding देगी। इसके के लिए 66 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

78. सरकार प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पहले चरण में 2025–2026 के दौरान जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में समस्त पारम्पारिक ईन्धन वाले वाहनों के स्थान पर ई-वाहनों को परिवर्तित करने की शुरूआत करेगी।

जल वायु व पर्यावरण

79. सरकार आपदाओं के जोखिमों को कम करने, फसलों के संरक्षण को बढ़ाने, पौष्टिक खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, राज्य सरकार जल संरक्षण के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में 100 जलवायु–संवेदनशील गाँवों की पहचान कर Climate-Smart Agriculture, और Renewable Energy Microgrids के माध्यम से विकास करने हेतु Climate Resilient Villages (CRV) Programme शुरू करेगी।

80. सरकार हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (HIMCOSTE) व समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश के सहयोग से चम्बा जिले में चार सरकारी संस्थानों और शिमला जिले में दो सरकारी संस्थानों में Dome Theater स्थापित किए जाएंगे, जिसमे Science और Astronomy शिक्षा तक पहुंच का विस्तार होगा।

81. प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सर्कुलर इकॉनोमी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार Deposit Refund System, Buyback Scheme, Advance Recycling सुविधाएं स्थापित करने और Biodegradable विकल्पों को प्रोत्साहित कर 2030 तक प्लास्टिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **"Plastic Neutral Himachal"** अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में राज्य स्तरीय संग्रह केंद्र स्थापित कर Extended Producer Responsibility (EPR) को लागू किया जाएगा।

82. Himachal Pradesh State Biodiversity Board के साथ सरकार द्वारा Biodiversity Conservation and Protection में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु एक Biodiversity Guardianship Program शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सरकार महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और निगरानी के लिए स्थानीय युवाओं को "Biodiversity Guardian" के रूप में नामित करेगी। इस कार्यक्रम के तहत विभाग युवाओं को Access Benefit Share Fund के तहत छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

शिक्षा

83. पिछले 2 वर्षों मे हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर आज तक चली आ रही पुरानी सोच को बदला है। हमने नये शिक्षण संस्थानों को खोलने व उन्हें Upgrade करने के स्थान पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत से शिक्षा संस्थान स्पष्ट सोच अथवा वैज्ञानिक आकलन के आधार पर नहीं खोले गए जिसके कारण पूरे प्रदेश में हजा़रों शिक्षण संस्थान ऐसे हो गये जिनके दो से तीन किलोमीटर के दायरे में उसी स्तर का दूसरा शिक्षण संस्थान भी काम कर रहा था। इतनी कम दूरी पर एक से अधिक सरकारी शिक्षण संस्थान होने से न केवल अध्यापकों और अन्य संसाधनों का अपर्याप्त इस्तेमाल हो रहा था बल्कि इन सभी संस्थानों में बच्चों की संख्या भी न्यूनतम स्तर

तक पहुंच गई। यहां तक कि 412 प्राईमरी स्कूल और 106 मिडल स्कूल ज़ीरो नामांकन(Zero Enrolment) के कारण बन्द हो गये। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और शिक्षा के क्षेत्र की आधारभूत आवश्यकता को समझते हुये शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण किया और स्कूल क्लस्टरों को क्रियाशील किया। पिछले वर्ष मैंने Institutions of Excellence को विकसित करने की बात की थी। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थानों को चिन्हित कर लिया गया है तथा इन में अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पहल से बच्चों की शिक्षा में सुधार देखा गया है। व्यवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जायेगा और उच्च शिक्षा संस्थानों का भी युक्तिकरण किया जायेगा।

84. प्रदेश में वर्ष 2001 से लगातार जन्म दर में कमी आई है और हमारी जन्म दर Replacement Level से काफी नीचे आ गई है। इसके परिणाम स्परूप स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2003 में पहली कक्षा में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या 1,47,045 थी जो 2023–24 में घट कर 97,427 रह गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन्म से सम्बाधित आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसलिये शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन समय की मांग है।

85. हम प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों का युक्तिकरण करते हुए बच्चों को निशुल्क छात्रावास अथवा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा कर Integrated और Composite स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। अगले वर्ष इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे।

86. सरकार द्वारा लिये गये दूरगामी निर्णयों के कारण प्राथमिक स्तर पर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार ने सभी स्कूलों को अभिभावकों के साथ

मिल कर स्कूलों में वर्दी चुनने का विकल्प दिया। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि प्रदेश में अभी तक 7 हज़ार 663 विद्यालयों ने अपने बच्चों के लिए मनपसंद वर्दी का चुनाव किया है।

87. हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र–छात्राओं और खेलकूद तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले बच्चों को विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है।

88. वर्ष 2025–2026 से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की Digital Attendance शुरू की जाएगी।

89. प्रदेश में 19 स्थानों पर **राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल** बनाए जा रहे है। इनके निर्माण के लिए 31 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए है। मैं निम्नलिखित स्थानों पर वर्तमान में कार्य कर रहे Government Senior Secondary Schools को प्रथम चरण में **राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल** के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूँ :

- गगरेट, अम्ब, हरोली, बंगाणा, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इन्दौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, ढलियारा, शिलाई, रिकांगपिओ (किन्नौर), केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिन्द्रनगर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा में प्री–नर्सरी से 12वीं कक्षा तक कम से कम 750 बच्चों वाले स्कूलों को भी **डे बोर्डिंग स्कूलों** के मापदण्डों पर विकसित किया जाएगा।

90. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए एक अलग निदेशालय बनाया जायेगा और कॉलेज

तथा उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों को देखने के लिए एक अलग निदेशालय का गठन किया जाएगा।

91. मैं सुजानपुर स्थित सैनिक स्कूल को Hostel की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रूपये की राशि दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

92. प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऊना और कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए 4 Hostel बनाए जाएंगे। साथ ही हमीरपुर और सुजानपुर में स्कूली लड़कियों के लिए Hostel बनाए जाएंगें।

93. H.P. State Higher Education Council राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करके प्रदेश मे उनके चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9 हज़ार 849 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा

94. उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज और नवाचार की संस्कृति विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, मुझे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक विचारों और पहलों को शुरु करने के लिए 2 करोड़ रुपये के समर्पित Innovation Fund की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

95. अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में राजकीय हाईड्रो इन्जीनियरिंग महाविद्यालय बन्दला में एम.टैक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Vehicle Technology) की कक्षाएं चलाई जाएगी।

96. जिला बिलासपुर के घुमारवीं में Digital University of Innovation, Entrepreneurship, Skill, and Vocational Studies की स्थापना सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP Mode) व Self Financing पर की जाएगी, जो एक डिजिटल रूप से कुशल और उद्यमशील कार्यबल को बढ़ावा देगी। यह विश्वविद्यालय Innovation

का केंद्र बनेगा और हमारे युवाओं को Competitive Global Environment के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा।

सड़कें व पुल

97. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में विशेष रूप से रेलवे और जल परिवहन के पर्याप्त नेटवर्क की अनुपस्थिति में एक मजबूत Road Network बहुत जरूरी है। अतः हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना जारी रखेगी।

98. मेरी सरकार 3 सौ 45 करोड़ रूपये की लागत से निम्न 6 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं का 2025–2026 में निर्माण कार्य शुरू करेगीः–

- नवगांव–बेरी
- सुजानपुर–टीहरा–सन्धोल
- हवल–हडसर–देहरी–पनाल्ठ–धार जरोट–नगरोटा सूरियां–बरियाल–देहरा–ज्वाली और गज खड्ड के उपर पुल
- बखरोट–करसोग–सनारली–सैंज
- टिक्कर जड़ोल–घान–ननखड़ी–खमाडी
- कुफरी–चैल

99. इसके अतिरिक्त NABARD के तहत भी 4 सौ 98 करोड़ 62 लाख रूपये की लागत से 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

100. मेरी सरकार द्वारा सभी कार्यों में खरीद के लिए e-Tender को प्रभावी बनाया है। इसमें निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है तथा कार्यों को Award करने का कुल समय जो पहले औसत 37 दिन था, अब 12 दिन हो गया है, जिससे कार्य आवंटन तथा निष्पादन में तेजी आएगी।

101. वर्ष 2025–2026 के लिए "**मुख्यमन्त्री सड़क योजना**" के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्व

102. अध्यक्ष महोदय, सुशासन के लिए स्वच्छ प्रशासन आवश्यक है। 2025–2026 के दौरान राजस्व विभाग का व्यापक Digitalization करके राजस्व सम्बन्धी सभी मामलों के शीघ्र निपटान के साथ–साथ पूरी प्रकिया में अच्छे शासन के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में मैं निम्न घोषणाएं करता हूँ :–

- सभी राजस्व न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जाएगा तथा प्रदेश में ई–राजस्व प्रणाली लागू की जाएगी। Revenue Court Management System(RMS) के अन्तर्गत एक मॉडयूल विकसित किया जाएगा जो नागरिकों से सम्बन्धित भूमि रिकॉर्ड को सीमाँकन और नामान्तरण से जुड़े मामलों के साथ मैप करेगा। इससे न केवल नागरिकों को राजस्व मामले डिजिटल तरीके से File करने में मदद मिलेगी बल्कि राजस्व अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफार्म पर अदालती कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी।

- नवीनतम हवाई सर्वेक्षण तकनीक (Aerial Survey Technology) के माध्यम से चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक जमीनी स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड तैयार किया जाएगा जिससे बेहतरीन शहरी नियोजन में मदद मिलेगी।

- डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से ततीमा(Maps) उपलब्ध करवाने हेतु **"भू–नक्शा"** एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों को अपने Maps प्राप्त करने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नही होगी।

103. सरकार ऑनलाइन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर शुरू करके म्यूटेशन की प्रक्रिया को डिजिटल करेगी, जिससे

इस प्रक्रिया की एक पेपरलेस प्रणाली स्थापित होगी। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होगा और म्यूटेशन को सत्यापित करने में होने वाली अनावश्यक देरी भी कम होगी।

104. आपदाओं से निपटने के लिए 3 हजार 645 पंचायतों में एक संगठित और सामुदायिक संचालित **"पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र"** की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र अन्तर जिला एजेन्सी समूह, समन्वय केन्द्रों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि समय रहते आपदा से निपटने की तैयारी की जा सके।

105. सरकार ने AFD के माध्यम से लगभग 892 करोड़ रूपये की लागत से आगामी पांच वर्षों के लिए Disaster Risk Reduction and Preparedness Project बनाया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आपदाओं से निपटने और उनकी प्रभावशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैंः–

- Multi Hazards जैसे की Landslides, Flash Floods, Clould Burst, GLOF इत्यादि के लिए Early Warning System का विकास और GIS पर आधरित Decision Support System ।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (State Disaster Response Force) के परिसरों की स्थापना।
- भूस्खलन रोकने और ढलानों को स्थिर करने के लिए Bio-Engineering उपायों का प्रोत्साहन।
- उप–मण्डल और तहसील स्तर पर भी "Disaster Risk Reduction Co-ordination Centre" स्थापित किए जाएंगे।
- HP State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authorities, State Emergency Operation Cell, District Emergency Operation Cells को सुदृढ़ किया जाएगा।

- कृषि और बागवानी के लिए जलवायु/मौसम पूर्वानुमान का विकास।
- जंगल की आग के खतरों को कम करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा।
- जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन से सम्बन्धित अध्ययन।
- भूकंप–प्रतिरोधी तकनीकों को बढ़ावा देना।
- Disaster Risk Reduction के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।
- Himalayan Disaster Risk Reduction Centre की स्थापना पालमपुर में की जाएगी।

सामाजिक कल्याण

106. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश वासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करने में विश्वास करती है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए मैं निम्न घोषणाएं करता हूँ :–

- वर्तमान में प्रदेश में 8 पैन्शन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिन पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक हज़ार 410 करोड़ रूपये खर्च किए गए, जिनसे 8 लाख 24 हज़ार 928 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 2025–2026 के दौरान सामाजिक पैन्शन योजना में 37 हज़ार नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा तथा इसके लिए लगभग 67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारी/पैन्शनभोगियों और आयकर दाता दिव्यांगजनों को छोड़कर सभी विशेष योग्यजन व्यक्तियों(दिव्यांगजन) जिनकी बैंचमार्क विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक है उनको सामाजिक सुरक्षा पैन्शन योजना (SSP) प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित

करवाएगा अपितु उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी सशक्त करेगा।

- सामाजिक सुरक्षा पैन्शन (SSP) के वितरण में पारदर्शिता और इसे प्रभावी बनाने के लिए आगामी वित वर्ष में एक End-to-End एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल/प्लेटफार्म लान्च किया जाएगा। इसके माध्यम से हिम परिवार रजिस्टर नकल, राजस्व रिकॉर्ड, आय प्रमाण पत्र आदि को ऑनलाइन Link किया जाएगा। इसी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग और Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board (HPBOCW) से NOC प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

107. सरकार द्वारा शुरू की गई "**इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना**" के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं। राज्य की सम्पदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को हर महीने 1500 रूपये इस योजना मे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुज़ारा करती हैं, उन्हें भी इस योजना के अर्न्तगत 1 जून 2025 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी पात्र बेटियाँ भी 1500 रूपये प्रति माह मिलने की हकदार होगीं। आने वाले समय में जो भी महिलाएं पंचायत द्वारा अनुमोदित की है, उनको चरणबद्ध तरीके से इस योजना से लाभन्वित किया जाएगा। विधवा बहनों की बेटियां भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने की पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त यदि विधवा बहनों की बेटियां Professional Courses के लिए पढ़ाई करना चाहें तो, सरकार उनकी पूरी फीस और संस्थान द्वारा स्वीकृत

Hostel Fees का व्यय वहन करेगी। यदि वे PG में रहना चाहें तो सरकार एक वर्ष में 10 माह के लिए 3000 रूपये प्रति माह प्रदान करेगी। इस योजना के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष के दौरान 200 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।

108. मैं **Institution for Children with Special Abilities** (ICSA) सुन्दरनगर की तर्ज़ पर हि0प्र0 राज्य बाल कल्याण परिषद् से विशेष योग्यजन बच्चों के लिए संस्थान ICSA ढली को कर्मचारियों सहित सरकार के अधीन लेने की घोषणा करता हूँ। इस कदम का लक्ष्य यह है कि इन बच्चों को और विकसित सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

109. सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (SJAY) के तहत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को नए मकान के निर्माण के लिए एक लाख 50 हज़ार की वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्माण लागत और Inflation को देखते हुए, सरकार इस योजना–अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी।

110. सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उददेश्य से अन्तर्जातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया जाएगा।

111. सरकार **"विकलांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन"** नामक उप योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख करेगी।

112. सरकार द्वारा **"मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना"** के तहत आगामी वित्त वर्ष में नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है,

जिस पर 5 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया जाएगा।

113. सरकार वर्तमान में **"वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना"** के अन्तर्गत 9 वृद्ध आश्रम चला रही है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 2025–2026 के दौरान प्रदेश के अन्य स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम/वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किए जाएंगे।

114. मैं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से स्वरोज़गार और विभिन्न लघु उद्यमों आदि के लिए कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय को मौजूदा 35 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रूपये करने की घोषणा करता हूँ।

115. सरकार वर्तमान में राज्य में जिला कुल्लू में दो व हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में एक–एक Integrated नशा मुक्ति केन्द्र चला रही है। राज्य में Drug Addiction और तस्करी की बढ़ती समस्या को देखते हुए और अधिक ऐसे केन्द्रों की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य में 3 और नशा रोकथाम एवं नशा मुक्ति–सह–पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

116. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण और बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पोषण सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने हेतु वचनबद्ध है।

117. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में Sex Ratio at Birth में लगातार सुधार हो रहा है तथा वर्ष 2023 में 947 के मुकाबले यह वर्ष 2024 में 964 हो गया। यह सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों तथा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। महोदय, मैं बीपीएल परिवार में जन्म लेने

वाली दो बालिकाओं के लिए **''इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना''** की घोषणा करता हूँ। यह **''बेटी है अनमोल योजना''** को और अधिक सशक्त करेगी। इसमें बालिका के जन्म पर 25000 रूपये की राशि बीमा कंपनी में जमा करने की व्यवस्था होगी, साथ ही बालिका के माता–पिता को जीवन बीमा का लाभ भी देय होगा जो कि प्रति अभिभावक दो लाख रूपये होगा। बीमा की मैच्योरिटी पर देय राशि बालिका को 18 या उसकी स्वेच्छा से 27 वर्ष तक की आयु तक दिए जाने का प्रावधान होगा।

118. अध्यक्ष महोदय, काम–काजी महिलाओं की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 2025–2026 में 132 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः सोलन, नीरी, दरुही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चनौर इंडस्ट्रियल एरिया और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 **Working Womens' Hostels** का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

119. अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की है। इस दृष्टि से बच्चों में शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मैं 1 अप्रैल 2025 से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को **''आंगनवाड़ी सह प्री–स्कूल''** के रूप में नामित करने की घोषणा करता हूँ। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में यथासंभव Co-locate किया जाएगा। इन स्कूलों में तीन से छह वर्ष के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा SCERT सोलन द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम तथा National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी।

120. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में हुई व्यापक वृद्धि के बावजूद छोटे बच्चों के स्वास्थ्य मानकों में आ रही गिरावट के कारणों को समझने की दृष्टि से सरकार ने पिछले दिनों एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें चर्चा उपरान्त देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की। कार्यशाला में यह तथ्य सामने आए कि युवा महिलाओं के बीच छोटे बच्चों के समुचित ब्रेस्टफीडिंग और पूरक भोजन तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही इन सिफारिशों को आकार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्षो से चल रहे पूरक पोषाहार कार्यक्रम में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अतः मैं इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक नई योजना **''इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना''** की घोषणा करता हूँ।

121. इस योजना के अन्तर्गत हर आंगनवाड़ी में पूरक पोषाहार को और अधिक पौष्टिक बनाने हेतु विशेषज्ञों की राय से पूरक पोषाहार को लाभार्थियों में आवंटित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां तक सम्भव हो पूरक पोषाहार का क्रय विकेंद्रीकृत किया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष 65 करोड़ रूपये अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा विभाग में वर्तमान में चल रहे सम्बन्धित कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित कर एक समेकित कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से एक Co-ordination कमेटी का गठन किया जाएगा। फील्ड लेवल पर आशा–वर्कर व आँगनवाड़ी–वर्कर के बीच भी बेहतर तालमेल बैठाया जाएगा व उनके द्वारा किए जा रहे Data Collection को पारस्परिक संवाद द्वारा अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया व डायरिया तथा अन्य जल जनित रोगों की रोकथाम के साथ–साथ सभी

स्टेकहोल्डर की जागरूकता, आउटरीच और प्रशिक्षण पर केंद्रित एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

122. सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर जिला ऊना में पायलट आधार पर चलाए जाने वाले WINGS प्रोजेक्ट (World-leading Innovative Study Programme) को पूरा सहयोग देगी ताकि हमारी महिलाओं व बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण संभव हो सके।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवं अन्य पिछड़ वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2 हज़ार 533 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

आयुष

123. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुष केवल एक चिकित्सा पद्धति ही नही है बल्कि प्राकृतिक जीवनशैली का एक तरीका भी है। अतः आम जनता को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए हमारी सरकार बहुत से कार्य कर रही है।

124. हमारी सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान जिला काँगड़ा में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू करेगी।

125. पायलट आधार पर पपरोला और शिमला के आयुष अस्पतालों में पर्यटकों और आम जनता के लिए वैलनेस पंचकर्मा शुरू किया जाएगा।

126. मैं **"आचार्य चरक योजना"** की शुरूआत करता हूँ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों को निःशुल्क जाँच और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रकार की निःशुल्क नैदानिक जाँच तथा आवश्यक औषधि सूची में शामिल 150 से अधिक आयुष दवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इससे प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पारम्परिक चिकित्सा सेवा मिलेगी और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान मिलेगा।

पुलिस/ कानून व्यवस्था एवं अग्निशमन

127. अध्यक्ष महोदय, कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। HP Anti Drug Act के प्रावधानों के माध्यम से वर्तमान समय में नशे से जूझ रहे लोगों के लिए Punitive Measures के स्थान पर पुर्नवास पर जोर दिया जाएगा ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। नशीली दवाओं के दुरूपयोग और तस्करी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

128. मैं 2025–2026 में Special Task Force (STF) बनाने की घोषणा करता हूँ, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी से सम्बन्धित गतिविधियों पर विराम लगाने हेतु कार्य करेगी।

129. संगठित अपराध सिण्डिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियन्त्रण और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियम **"Himachal Pradesh Prevention of Continuing Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act, 2025"** लाया जाएगा।

130. पर्यटन सुरक्षा में सुधार एवं पुलिस जवानों के प्रभावी विकास तथा आधुनिक आपराधिक जांच की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में पुलिस स्टेशनों/डैस्क को स्थापित किया जाएगा और सम्बन्धित थानों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

131. अध्यक्ष महोदय, अग्निशमन विभाग में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना के अगले चरण में 21 करोड़ के व्यय के साथ मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- राजगढ़ जिला सिरमौर और कण्डाघाट जिला सोलन में दमकल केंद्र खोले जाएंगे।
- नादौन, इन्दौरा, राजगढ़, और कण्डाघाट में 8 नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करने और 20 से 22 वर्ष पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के

स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदा जाएगा।

- 16 Quick Response Vehicles, प्रशिक्षण और जनसमुदाय को जागरूकता प्रदान करने के लिए 2 बसें और विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों को खरीदा जाएगा।

132. 2025–2026 के दौरान उप दमकल केन्द्र काज़ा व कुमारसैन; जोगिन्द्रनगर, फतेहपुर व आनी की दमकल चौकियों के विभागीय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

उद्योग

133. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प है। 2024–25 में **बल्क ड्रग पार्क** में 2 सौ 34 करोड़ रूपये की राशि के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। आगामी वर्ष में इस परियोजना के कार्य को सुचारू रखने के लिए केन्द्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार बजट का प्रावधान किया जाएगा।

134. प्रदेश में बरसात के कारण बनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2024–2025 में 149 औद्यौगिक प्रस्तावों को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई जिनमें 3 हज़ार 84 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा तथा 15 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। 2025–2026 के दौरान प्रदेश की औद्यौगिक नीति में मूलभूत बदलाव किए जाएंगे। निवेशकों के लिए सभी औपचारिकताओं को न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा तथा सभी आवश्यक Clearances 2 माह के भीतर सुनिश्चित की जाएंगी। निवेशकों के लिए एक Friendly Environment बनाने में सरकार केवल Enabler का रोल निभाएगी। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन व इलैक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में Investor Outreach Programmes आयोजित किए जाएंगे।

135. हमारी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में Raising and Accelerating MSME Performance(RAMP) Scheme के अन्तर्गत 1 हज़ार 642 करोड़ रूपये की लागत के कार्यक्रम के पहले चरण में 109 करोड़ रूपये की योजना का निष्पादन कार्य प्रगति पर है।

136. मेरी सरकार राज्य की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी उद्योगों, उद्योगपतियों, छोटे, मध्यम व बड़े उद्यमियों की पूरी सराहना करती है। सरकार इस बात से भी भली–भान्ति परिचित है कि एक समृद्ध हिमाचल केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की ताकत पर ही निर्मित हो सकता है। मुझे पता है कि उद्योगों और उद्यमियों को निवेश के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ केवल Procedural हैं व शीघ्र ही हल किए जा सकते हैं। अतः सभी हितधारकों को एक मंच पर नियमित रूप से मिलकर स्थिति की समीक्षा करने और व्यवसाय को सरल बनाने के लिए एक Institutionalised Dialogue Mechanism की आवश्यकता है। मैं घोषणा करता हूँ कि एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करेगा, नियमित रूप से बैठकें करेगा और सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करेगा।

137. पिछले दो वर्षों में मेरी सरकार ने दिल्ली हाट में सर्दियों के महीनों के दौरान हिम उत्सव का आयोजन किया है, जो उल्लेखनीय सफलता के साथ संपन्न हुआ। इसने हिमाचल के उत्पादों को दिल्ली के high paying clientele of Delhi से परिचित कराया है। परिणाम उत्साहजनक हैं, जिससे ग्रामीण कारीगरों को परिपक्व लाभ प्राप्त हुआ है। मैं घोषणा करता हूँ कि हिम उत्सव एक वार्षिक आयोजन होगा।

138. पिछले वर्ष उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को एक रूपये प्रति यूनिट की दर से Withdraw किया

गया था। मैं 66 KV या उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी देने की घोषणा करता हूँ। यह सब्सिडी वर्ष में दो बार अक्टूबर और मार्च के महीने में DBT के माध्यम से दी जाएगी।

जनजातीय विकास

139. हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों और यहां के लोगों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक और संवेदनशील है। प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज जनजातीय क्षेत्रों में दूसरे भागों से अधिक सम्पन्नता और समृद्धि देखी जा सकती है। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का औसत प्रदेश के अन्य ज़िलों से अधिक है। इन क्षेत्रों में न केवल आर्थिक सम्पन्नता है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र प्रदेश में अग्रणी है। इन क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात प्रदेश के अन्य भागों से अच्छा है। मैं प्रदेश के जनजातीय लोगों को इन तमाम उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ।

140. सोलर ऊर्जा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, तीसा और अन्य चिन्हित स्थानों पर निजी क्षेत्र में 250 किलोवॉट से एक मेगावाट तक की सोर परियोजना स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत का ब्याज उपदान प्रदान करेगी। गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सोलर परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत तथा एक मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं पर 3 प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जाएगा।

141. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके साथ विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि इस

अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं को गति मिल सकें।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन

142. अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुगम बनाने तथा सरकारी सेवाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्प है। आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 6 हज़ार Transactions होती हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान नवम्बर, 2024 तक 14 लाख 67 हज़ार से अधिक Transactions हो चुकी हैं। इस पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें Artificial Intelligence (AI) का प्रयोग किया जाएगा।

143. हिमाचल में पहली बार **"हिम परिवार परियोजना"** राज्य के सभी नागरिकों का एकीकृत डेटाबेस बनाने की दिशा में हमारी सरकार की एक पहल है। अब तक इस परियोजना के तहत 19 लाख 28 हज़ार 270 परिवारों और 76 लाख 31 हज़ार 682 सदस्यों को हिम परिवार आईडी दी गई है। 2025–2026 के दौरान हिम परिवार आईडी को विभिन्न विभागीय योजनाओं के डेटाबेस में एकीकृत किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों की पहचान सम्भव होगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सका कि कोई भी पात्र लाभार्थी किसी योजना के लाभ से वन्चित न रह जाए। इसके अतिरिक्त, "हिम एक्सेस" नामक एक State Single Sign-On (SSO) System लान्च किया गया है, जो 30 से अधिक Citizen-Centric Services को जोड़कर सेवा वितरण और अनुभव में प्रदान करेगा। यह परियोजना लाभ वितरण प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाएगी, बार–बार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को कम करेगी, और पात्र व्यक्यिों तक शीघ्र लाभ पहुँचाएगी। यह प्रणाली भविष्य की नीतियों के लिए सटीक डेटा भी उपलब्ध कराएगी।

144. प्रदेश में निवेश एवं उद्योग संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में शिमला के मैहली और कांगडा के चैतडू में स्थापित किए जा रहे Software Technology

Park(STPI) पर कार्य पूरा किया जाएगा। इससे लगभग 500 से 650 युवाओं को नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

145. अध्यक्ष महोदय, उभरती प्रौद्यौगिकियों का उपयोग जहां एक ओर जन साधारण के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों की भी अपार सम्भावनाएं है। अतः इस दिशा में सरकार ने **"Green Himachal Vision"** के लक्ष्य को 2027 तक पूरा करने के दृष्टिगत प्रदेश में Drone Technology को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार लोगों की सुविधा हेतु Drone Taxi सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी जोकि विशेषकर प्रदेश के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सामाग्री/कृषि उत्पाद/दवाईयाँ इत्यादि को पहुचाने हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नीति के अन्तर्गत Drone Technology Intervention से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी आधुनिकीकरण सम्भव हो सकेगा। इसके लिए जिला हमीरपुर, मण्डी और कांगड़ा में Drone Stations स्थापित किए जाएंगे।

हाऊसिंग

146. अध्यक्ष महोदय, 2025-2026 के दौरान हिमुडा के माध्यम से 1 सौ 20 करोड़ रूपये की लागत से बसाल(बिलासपुर) और बिन्द्रावन (पालमपुर) में आवासीय कॉलोनियाँ तथा रामपुर फेज-3, रजवाड़ी (मण्डी) व धर्मपुर (सोलन) में लगभग 82 फ्लैटों और 137 रिहायशी प्लाटों को विकसित करेगी।

147. मै 2025-2026 में हिमुडा द्वारा विकासनगर, शिमला में 250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक विशाल व्यवसायिक परिसर के निर्माण की घोषणा करता हूँ। इस व्यवसायिक परिसर को दो भागों में Plan किया जाएगा, जिसमें एक हिस्सा सरकारी दफ्तरों व दूसरे हिस्से को Commercial Use के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल

148. अध्यक्ष महोदय, मैं खेलों को बढ़ावा देने हेतु 2025–2026 के दौरान निम्न खेल अधोसंरचना के निर्माण की घोषणा करता हूँः–

- बिलासपुर के लूहणू में 100 बिस्तरों वाला खेल छात्रावास।
- जिला हमीरपुर के खरीड़ी में 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास।
- शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुद्देशीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- सोलन में इण्डोर स्टेडियम के साथ–साथ रिंकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण।
- हमीरपुर तथा सुजानपुर में Synthetic Track and Field सुविधा का निर्माण।

परिवहन

149. अध्यक्ष महोदय, सड़क यातायात प्रदेश में यातायात का मुख्य साधन है। दूर–दराज़ के इलाकों में भी बस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। लोगों को स्वच्छ एवं Green Transport सेवाएं प्रदान कराने की दिशा में सरकार द्वारा डीज़ल बसों को ई–बसों में बदलने की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रियाधीन e-Buses की खरीद के अतिरिक्त 2025–2026 में 500 और e-Buses खरीदी जाएंगी। साथ ही चार्जिंग Infrastructure की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम ने चार्जिंग ई–स्टेशन विकसित किए है तथा विभिन्न स्थानों पर इन्हे बनाने की प्रक्रिया जारी है।

150. परिवहन निगम द्वारा जनता की सुविधा के लिए शिमला में ऑनलाईन पास सुविधा शुरू कर दी है तथा इसे प्रदेश के अन्य स्थानों में शुरू करने हेतु Software तैयार कर शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

151. सरकार द्वारा शिमला शहर में यातायात की समस्या एवं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए 1 हज़ार 546 करोड़ 40 लाख रूपये की लागत से 14.79 किलो मीटर लम्बी रोपवे की एक शहरी परिवहन परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य New Development Bank के साथ समझौता ज्ञापन Sign होने के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा तथा इसे 4 वर्षों में पूर्ण करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

152. शिमला शहर में बढ़ते यातायात की समस्या का एक कारण निजी वाहनों का बढ़ना भी है। इसी के मध्यनज़र हमारी सरकार Youth, Businesspersons, Tourists, High End Passengers etc. को ध्यान में रखकर पायलट आधार पर Luxury Vehicles को चयनित रूटों पर चलाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा Viability Gap Funding के तहत 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

153. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रेल विस्तार कार्यों को हमारी सरकार द्वारा गति दी जा रही है। प्रदेश में भानुपल्ली–बिलासपुर तथा बद्दी–चण्डीगढ़ रेल लाइनों का कार्य ज़ोरों पर है। मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि भानुपल्ली–बिलासपुर रेल लाइन की कुल लागत लगभग 10 हज़ार करोड़ रूपये है, जिसमें से भू–अधिग्रहण की लागत 1 हजार 200 करोड़ रूपये से अधिक है। आपको आश्चर्य होगा कि भू–अधिग्रहण के लिए भारत सरकार द्वारा केवल 52 करोड़ रूपये प्रदान किए गए हैं तथा शेष राशि लगभग 1 हज़ार 150 करोड़ रूपये प्रदेश सरकार द्वारा वहन किए जाने हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक कुल 848 करोड़ रूपये की राशि दी जा चुकी है।

154. 30.28 किलोमीटर लम्बी चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाईन के भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश द्वारा वहन किया जा रहा है। इसकी कुल लागत लगभग 1 हज़ार 600 करोड़ रूपये है, जिसमें से भू–अधिग्रहण की लागत

लगभग 600 करोड़ रूपये से अधिक है। इस रेल लाईन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 348 करोड़ रूपये दिए जा चुके है।

155. इस प्रकार भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी तथा चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाईनों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है, जिसमें से 392 करोड़ रुपये की राशि तो दो सालों में कांग्रेस की वर्तमान सरकार द्वारा दी गई है।

156. अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान मैं परिवहन के क्षेत्र में निम्न कार्य करने की घोषणा करता हूँ :–

- ऊना जिले के हरोली में पहला Automatic Driving Test Track स्थापित किया जाएगा।
- जलमार्गों में जैटीज़ आदि का विकास और क्रूज पर्यटन, जल क्रीड़ा गतिविधियों और जल परिवहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 80 पेट्रोल पम्पों पर ई–वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू किए जाएंगे और ग्रीन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर PPP मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

शहरी विकास

157. अध्यक्ष महोदय, नव गठित/उन्नयित शहरी स्थानीय निकायों के विलय किए गए क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सेवाएं जैसे सड़क, रास्ते, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज, स्वच्छता, पार्क, पार्किंग आदि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार 2025–2026 के दौरान कुल 10 करोड़ 75 लाख रूपये की विकासात्मक अनुदान की राशि जारी करेगी। जिसमें नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए प्रत्येक को एक करोड़, नगर परिषद नादौन, बैजनाथ–पपरोला और सुन्नी के लिए 25 लाख प्रत्येक तथा नवगठित 14 नगर पंचायतों (कोटला, बंगाणा, बनीखेत, खुंडियां, नगरोटा सूरियां, झंडूता, बलद्वाड़ा, कुनिहार, धर्मपुर, सन्धोल, स्वारघाट,

भोरंज, शिलाई व बरसर) के लिए 50 लाख प्रत्येक के रूप में प्रदान की जाएगी। मैं जनता को यह भी अश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि नव गठित शहरी निकायों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्षो तक Property Tax में छूट प्रदान की गई है तथा पानी के रेट भी पहले के समान ही रहेगें।

158. सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से लगभग 44 सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिन्हें State Project Monitoring Unit (SPMU) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से UPYOG प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।

159. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने शहरीकरण का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है क्योंकि यह राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर भी Tier-I शहरों को Decongest करके, Tier-II और Tier-III शहरों के विकास पर बल दिया जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में हमारी सरकार वर्तमान विकास योजनाओं का पुनर्निरीक्षण तथा महत्वपूर्ण शहरी/पर्यटक क्षेत्रों में **"Business District Zone"** की स्थापना पर विचार करेगी।

160. सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्र के छोटे फल–सब्जी विक्रेताओं, चाय दुकानदारों, नाई की दुकानों, पान की दुकानों, जूता मुरम्मत की दुकानों, चाट, टिक्की, चना इत्यादि की दुकानों और खोमचे वालो, छोटे ढाबा मालिकों और अन्य छोटे परचून दुकानदारों के लिए **"मुख्यमन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना"** में लचीलापन लाते इसका विस्तार करेगी। इस योजना के तहत Distressed छोटे दुकानदारों जिन का Annual Turnover 10 लाख रुपये से कम है; को बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपये तक के One Time Settlement(OTS) की सुविधा दी जाएगी व Loan पर लगने वाले Interest को सरकार वहन करेगी। इस योजना से विक्रेता अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे। यह योजना न केवल इन विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी, अपितु राज्य के लघु व्यापारियों को सशक्त बनाने और

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

161. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः–

- महापौर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उप–महापौर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 19,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- काउंसलर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- अध्यक्ष, नगर परिषद को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- पार्षद, नगर परिषद को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- प्रधान, नगर पंचायत को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उप–प्रधान, नगर पंचायत को 400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- सदस्य, नगर पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

शहरी विकास के क्षेत्र में कुल 656 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

162. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के ठण्डे क्षेत्रों में Antifreeze और शीतकालीन जलापूर्ति योजनाओं के तहत जिला लाहौल स्पिति के लिए 27 करोड़ रूपये की लागत से 20 Water Supply Schemes और किन्नौर जिले में 72 करोड़ रूपये की लागत से 6 Water Supply Schemes का कार्य आरम्भ किया जाएगा। इस वर्ष नादौन, भोरन्ज, अमलेहड़ और हरोली में 4 Water Supply Schemes और बद्दी के लिए एक Sewerage Scheme का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

163. 298 करोड़ 87 लाख की अनुमानित लागत से 17 नगरों (मण्डी, ठियोग, राजगढ़, चम्बा, हमीरपुर, सुन्नी, रामपुर, डलहौज़ी, अम्ब, भुन्तर, नाहन, ज्वाली, बैजनाथ, अर्की, निरमण्ड, पालमपुर और जोगिन्द्रनगर) में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 11 नगरों में कार्य प्रगति पर है तथा शेष नगरों में कार्य वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2025-2026 में ही 9 अन्य नगरों क्रमशः भुन्तर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निरमण्ड, जोगिन्द्रनगर, शाहपुर, भटियात और करसोग में कुल 167 करोड़ रूपये की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा।

164. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 पेयजल आपूर्ति प्रणाली के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक क्षेत्र को चिन्हित (कुल 12) किया गया। इनमें से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 5 क्षेत्रों कम्रशः GWSS रामपुर(वार्ड न0 6 और 7), GWSS चम्बा(वार्ड न0 10), LWSS नालागढ़(वार्ड न0 7), LWSS घुमारवीं(वार्ड न0 2 और 5), व LWSS नादौन नगर में कार्य प्रगति पर है तथा शेष क्षेत्रों में शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

165. प्रदेश में 58 स्थानीय शहरी निकायों में जलशक्ति विभाग द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इनमें

से 23 नगरों में उन्नयन और सुधार कार्य चल रहे हैं। 9 नगरों की परियोजनाओं पर कार्य वित्तीय वर्ष 2025–2026 में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 नगरों (नेरवा, चिड़गांव, कण्डाघाट और टाहलीवाल) का उन्नयन प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

166. हमारी सरकार NDB के द्वारा वित्त पोषित **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन परियोजना** के तहत 7 सौ 45 करोड़ की लागत से 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हज़ार 663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इन सभी योजनाओं का कार्य 2025–2026 के अन्त तक पूरा किया जाएगा।

167. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन एवं आजीविका परियोजना के तहत लगभग एक हज़ार 62 करोड़ से अधिक की लागत से 10 जिलों की 2471 बस्तियों में लगाए जा रहे 79 हज़ार 282 Functional House Hold Tap Connection(FHTCs) का 43 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

168. हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मैं "**मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना**" की घोषणा करता हूँ। योजना में नवीनतम तकनीकों जैसे Ozonation, UV filtration, RO, और नैनो फिल्ट्रेशन इत्यादि का उपयोग कर जल शोधन कर स्वच्छ जल हिमाचल की जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। घरेलू और व्यावसायिक जल आपूर्ति योजनाओं का भी उन्नयन किया जाएगा ताकि उच्च गुणवत्ता वाला जल लोगों तक पहुंच सके। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और जल जनित बीमारियों की रोकथाम में और मदद मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

169. हमारी सरकार द्वारा लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में अगला कदम बढ़ाते

हुए जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी, जस्वां, प्रागपुर व देहरा में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 43 करोड़ रूपये की लागत से Drinking Water Treatment Plants लगाए जाऐंगे।

170. प्रदेश के 10 जिलों में (किन्नौर और लाहौल–स्पिति को छोड़कर) 291 चयनित योजनाओं में सेन्सर आधारित Real Time Monitoring System (Internet of Things) स्थापित की जा रही है। जिसके द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता, मात्रा की नियमित निगरानी की जाएगी।

171. हमारी सरकार द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक और सभी जिला स्तर पर 14 Bacteriological मापदण्डों लिए National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL) से मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न जल आपूर्ति, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं में Green Energy का प्रयोग करने के लिए सौर पेनलों की स्थापना हिम ऊर्जा के माध्यम से की जानी प्रस्तावित है।

172. प्रदेश में 6 नगरों (भोटा, सन्तोखगढ़, तलाई, बैजनाथ–पपरोला, नेरचौक और बंजार) जहां सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नही है, उनमें सीवरेज योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। 5 नगरों(नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर और बिलासपुर) के लिए सीवरेज योजनाओं का कार्य 2025–2026 में आरम्भ कर दिया जाएगा। इस सुविधा से वंचित शेष 9 नगरों हेतु भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे है।

173. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने वर्तमान में 41 सीवरेज योजनाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत किया है, जिसमें से कांगड़ा, मण्डी, चम्बा और किन्नौर ज़िलों के 14 कस्बों में सीवरेज योजनाओं पर कार्य 2025–2026 में शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

174. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समूचे प्रदेश में चिकित्सा संस्थान तथा मैडिकल कॉलेजों में आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। महोदय, मैने पहले बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को **"आदर्श स्वास्थ्य संस्थान"** के रूप में विकसित करने घोषणा की थी। हमारी सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप स्वास्थ्य के क्षेत्र में गत दो वर्षो के दौरान किए गए कार्यों के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। 2025-2026 के दौरान सरकार द्वारा इन स्वास्थ्य संस्थानों में निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगीः

- 69 संस्थानों में से 20 संस्थानों में डॉयलेसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा शेष बचे संस्थानों में लगभग 45 करोड़ की लागत से 49 यूनिट स्थापित किए जाएगें।
- आगामी वित्त वर्ष में 11 संस्थानों घवांडल, चवाड़ी, भोरंज, नादौन, तयारा, जयसिंहपुर, पधर, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली व अम्ब में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
- बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिलों में 17 **Newborn Stabilization Units** स्थापित की जाएंगी।

175. हमारी सरकार द्वारा लोगों को अत्याधुनिक Medical Technology से लैस AIIMS-Delhi के स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से 45 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से AIMSS, Chamiana, Shimla व टॉण्डा मैडिकल कॉलेज, कांगड़ा में Robotic Surgery स्थापित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर दी जाएगी। IGMC Shimla में 20 करोड़ 73 लाख 12 हज़ार रूपये की लागत से Positron Emission Tomography (PET) Scan की सुविधाएं अगले तीन महीनों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से आवश्यक Infrastructure सहित MRI की

अत्याधुनिक मशीनें IGMC Shimla, AIMSS Chamiana, Shimla, Govt. Medical College Hamirpur तथा Govt Medical College Ner Chowk में स्थापित की जाएंगी।

176. अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी **"मैडिकल कॉलेजों"** एवं **"आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों"** में विश्व स्तरीय उपचार उपलब्ध करवाने हेतु बहुत जल्द और अधिक उच्च गुणवत्ता वाले अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी(JICA) के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता हेतु 1 हज़ार 700 करोड़ रूपये सुनिश्चित किए जा रहे है।

177. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज मण्डी में हृदय रोगियों की सुविधा के लिए Cath. Lab की स्थापना की जाएगी।

178. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के हमारे प्रयासों के तहत, 10 नए Health and Wellness Centres की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र, निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे।

179. प्रदेश के Medical Colleges तथा AIMSS चमियाना में PG को Senior Resident/Tutor Specialist को वर्तमान में वज़ीफे के रूपये में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की पढ़ाई हेतु प्रदान की जा रही राशि क्रमशः 60 हज़ार, 62 हज़ार व 65 हज़ार को बढ़ाकर एक लाख रूपये करने की घोषणा करता हूँ तथा साथ ही DNB-Super Specialist & Sr. Residents-Super Specialist(D.M./M.Ch.) के वज़ीफे की राशि को भी वर्तमान दर क्रमशः 60 हज़ार, 62 हज़ार व 65 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रूपये करने की घोषणा करता हूँ।

180. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने व मरीजों की देख–भाल हेतु "**रोगी मित्र योजना**" के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक हज़ार के करीब रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन

रोगी मित्रों को 15 हज़ार मासिक मानदेय देय होगा, जिस पर राज्य सरकार 18 करोड़ रूपये व्यय करेगी।

181. मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश में ऑउटसोर्स पर नियुक्त Operation Theater Assistant का मासिक मानदेय 7 हज़ार 1 सौ अस्सी रूपये की वृद्धि के साथ 17 हज़ार 820 रूपये से तथा Radiographer का मासिक मानदेय 11 हजार 9 सौ रूपये की वृद्धि के साथ 13 हज़ार 100 रूपये से बढाकर 25 हज़ार रूपये किया जाएगा।

182. हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का जनता के घर–द्वार से ही लाभ लेने व अस्पतालों की लम्बी कतारों से निज़ात पाने के लिए **सुगम स्वास्थ्य** नाम की नई App शुरू करेगी प्रदेश के 6 मैडिकल कॉलेज अस्पतालों, AIMSS चम्याणा, कमला नेहरू अस्पताल, 9 जिला अस्पतालों तथा 36 जिला अस्पतालों में उपचार हेतु हर प्रदेशवासी घर से ही ऑन लाईन Appointment ले सकता है।

183. अध्यक्ष महोदय, जैसा की आपको स्मरण होगा कि मैंने वर्ष 2023–2024 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार टाइप–1 डायबिटीज़ से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवाएगी। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वित्त वर्ष से यह सुविधा अब 27 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

184. सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के दौरान Palliative Care (राष्ट्रीय प्रशामक स्वास्थ्य) देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल सरकार गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 12 हज़ार रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेवाएं प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के साथ–साथ सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को पैलिएटिव केयर (Palliative Care) हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसमें स्वास्थ्य कर्मी

मरीजों के घर जाकर उपचार करेंगे और परिवार के सदस्यों को देखभाल का प्रशिक्षण देंगे।

185. वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए **"मुख्यमन्त्री वृद्धजन देखभाल योजना"** नामक नई योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टॉफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करेगें, जिससे उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सकेगा। यह पहल सरकार की वृद्धजन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

186. बच्चों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए हमीरपुर जिले में आई0आई0टी0 मुम्बई के समन्वय से पायलट आधार पर 6 माह से अधिक आयु के बच्चों के स्तनपान की ईम्प्रोवाइज (Improvise) तकनीक और पूरक आहार पर अध्ययन किया जाएगा।

187. कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण दुर्गम और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा।

188. प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन को आसान बनाने के लिए **"राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र"** (SHSRC) स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण, और गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देगा।

189. प्रदेश में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए, कमला नेहरू अस्पताल शिमला और मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मण्डी में Command Centre

स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अन्य सभी Sick Newborn Care Units को इन Command Centre से Tele-Consultation के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे बीमार नवजात बच्चों की देखभाल और अधिक प्रभावी ढ़ंग से हो सकेगी।

190. प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 25 Advanced Life Support एम्बुलेंस की खरीद की जाएगी।

191. हम सभी, राज्य में बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों को लेकर बहुत चिंतित हैं। मेरी सरकार ने इस समस्या के आपूर्ति और मांग पक्ष, दोनों पर गंभीरता से काम किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें अपने बच्चों को अपराधी न मान कर पीड़ित मानना चाहिए। हमें ऐसे बच्चों के पुनर्वास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। अतः इस सन्दर्भ में निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Drug Dependence Prevention, De-addiction, and Rehabilitation Board का गठन मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में करेगी।
- सरकार PGIMER चंडीगढ़ और AIIMS नई दिल्ली के परामर्श से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और पुनर्वास हेतु एक Action Plan विकसित करेगी।
- Action Plan का महत्वपूर्ण हिस्सा एक राज्य–व्यापी जागरूकता और समुदायिक लामबंदी अभियान होगा, जिसमें पंचायतों, धार्मिक/सांस्कृतिक संगठनों, युवा क्लबों, एनसीसी, एनएसएस, शिक्षकों, महिलाओं के समूहों और NGO सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। इस में स्थानीय चैंपियन (खिलाड़ी, प्रभावशाली व्यक्ति, युवा आइकन और अन्य) शामिल किए जाएंगे। सामुदायिक रेडियो, स्थानीय

प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और Public Events का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

- मैडिकल कॉलेज, टाण्डा में एक Drug De-addiction and Rehabilitation नोडल केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथा चरणबद्ध तरीके से इन केंद्रों का राज्य–व्यापी विस्तारीकरण किया जाएगा।
- सिरमौर जिले में एक Drug De addiction and Rehabilitation केंद्र चालू किया जाएगा।
- क्षेत्रीय/जिला/मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार डि–एडिक्शन बैडस की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- डि–एडिक्शन देखभाल में विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, सी0एच0ओ0 और अन्य प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- Psychiatrist, Clinical Psychologists, और Psychiatric Social Worker के पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मनोचिकित्सा में PG सीटों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- नीति आयोग उन जिलों में नशा उपचार सुविधाओं (ATFs) के लिए योजनाएँ तैयार करने में सरकार की सहायता करेगा जहाँ ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं।
- सरकार नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश में **"स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम"** के तहत, यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के डॉक्टर और पैरामैडिकल स्टॉफ नजदीकी स्कूलों में नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जांच के साथ–साथ Counselling-cum-Awareness Session भी आयोजित करेगें जोकि छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। इस योजना की प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

उपमण्डल स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी करेंगे।

192. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि Internet के इस युग में बड़ी संख्या में जनसंख्या को सही और निरन्तर नींद नहीं मिलती है। यदि इस समस्या का समय पर निदान और उपचार नहीं किया गया तो यह अन्य विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। अतः एक उद्भव और गंभीर परिणामों वाले महत्वपूर्ण विकार **Obstructive Sleep Apnea** (नींद में रुकावट), में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए सरकार PGIMER चंडीगढ़ में राज्य के मेडिकल कालेजों के चयनित संकाय को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

193. देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की तरह, राज्य के स्वास्थ्य संस्थान भी मरीजों की भारी भीड़ को प्रबंधित करने में संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार एक कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें स्थानीय शिक्षण संस्थानों के एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) के छात्रों को चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बेहतर अस्पताल प्रबंधन, मरीजों के लिए एक सुगम अनुभव और छात्रों व युवाओं में करुणा और स्वैच्छिक सेवा की भावना का विकास सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 3 हज़ार 481 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

ऊर्जा

194. सरकार का लक्ष्य 2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनाना है। HPPCL के माध्यम से लगभग 626 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में है।

- 200 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कांगड़ा डमटाल में लगाया जाएगा जिसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे सालाना

320 Million Units बिजली का उत्पादन होगा और प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

- **"ग्रीन पंचायत योजना"** के तहत 100 पंचायतों में 500–500 किलोवॉट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।

195. शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना(450 मेगावाट) पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है। सरकार ने कार्य को गति दी है। अब इस परियोजना के दिसम्बर, 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से सालाना लगभग एक हज़ार करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

196. एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना (130 मेगावाट) की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा जून, 2026 तक परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 350 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

197. पम्प भण्डारण परियोजनाओं से बिजली क्षेत्र के विकास की गति में वृद्धि होगी। प्रारम्भ में HPPCL को रेणुकाजी (1630 मेगावाट) और थाना–प्लाउन (150 मेगावाट) परियोजनाएं आबंटित की गई है। ये परियोजनाएं एक ओर Hydro Battery की तरह काम करेगी और Grid Stability को बढ़ाएगी जिससे अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा।

198. इसके अलावा Pump Storage Project (PSP) की स्थापना के लिए बीबीएमबी (13000 मेगावाट), एसजेवीएनएल (2500 मेगावाट), एनटीपीसी (2400 मेगावाट) और निजी उत्पादकों (2000 मेगावाट) से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

199. प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में पुनः तेजी लाने के लिए प्रयासरत है। हमने इस क्षेत्र की

समस्याओं का अध्ययन करने और उनके समाधान का सुझाव देने के लिए कैबिनेट सब–कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौप दी हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करेंगे।

200. हमने प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के उपक्रमों को उर्जा क्षेत्र में निवेश का आमन्त्रण दिया है। तेलंगाना सरकार ने प्रदेश में Hydro Projects में निवेश में रूचि दिखाई है। शीघ्र ही आपसी चर्चा के बाद हम तेलंगाना सरकार की Generation Company के साथ इस दिशा में आगे बढेंगे और MoU के माध्यम से चिन्हित परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करेंगें। हम अगले वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ाएंगे और ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगें।

201. बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में कांगू (जिला मण्डी) और टहलीवाल (जिला ऊना) में 220 केवी सब–स्टेशन में कार्य को पूर्ण करने का इस वर्ष लक्ष्य रखा गया है। इनकी कुल लागत 103 करोड़ रूपये होगी। इसके अलावा 82 करोड़ रूपये के निवेश से 2025–26 में धर्मपुर (जिला मण्डी) और बरसैनी (जिला कुल्लू) में 132 केवी के दो सब–स्टेशन के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की इस योजना से 426 एम.वी.ए. तक परिवर्तन क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार 2025–26 के दौरान 78 सर्किट किलोमीटर ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन का कार्य भी समाप्त करेगी जिसमें 132 केवी बरसैनी–चरोर लाइन (जिला कुल्लू) की 76 सर्किट किलोमीटर और 400 केवी कुटेहर–लिलो (जिला चम्बा) 2 सर्किट किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जिला ऊना में 200 एम.वी.ए. 220/132 केवी सब–स्टेशन जिनकी अनुमानित लागत 88.22 करोड़ है का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

202. उपभोक्ताओं को Quality Power Supply सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से आवश्यक

Infrastructure विकसित किया जाएगा। इसकी शुरूआत करते हुए कांगड़ा जिला के गनोग(नूरपुर), करला कोटला(देहरा), मझीण(ज्वालामुखी), मोकी(इन्दौरा), समलोटी (नगरोटा बगवां) और थेर(ज्वालामुखी) में आगामी वित्त वर्ष में 33KVA/11KVA के 6 Sub Station बनाए जाएगें।

ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 905 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

भाषा एवं संस्कृति

203. वित्त वर्ष 2025-2026 में प्रदेश के पारम्पारिक वास्तुशिल्प एवं व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए Bantony Castle शिमला के परिसर में दिल्ली हाट की तर्ज़ पर हि0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/शिल्पकारों हेतु स्टॉल स्थापित किए जाएंगें।

204. प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे मन्दिरों को वार्षिक आधार पर धूप बत्ती के लिए अनुदान दिया जाता रहा है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान सरकार राज्य समर्थित इन मन्दिरों को वर्तमान में दी जा रही अनुदान की राशि को दोगुना करेगी।

205. कुल्लू के नग्गर में अन्तर्राष्ट्रीय रौरिक मेमोरियल ट्रस्ट है। यह पर्यटन का मुख्य केन्द्र है और साथ ही यह भारत और रूस की मैत्री का भी प्रतीक है। इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और इसका मास्टर प्लान बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को वित्त पोषण के लिए भेजा जाएगा। मैं इस ट्रस्ट के बेहतर प्रबन्धन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से 15 लाख रूपये का वार्षिक अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

सैनिक कल्याण

206. गत वर्ष की भान्ति हमारी सरकार 2025-26 में भी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता पर भरा जाए।

207. मैं Sainik School में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाली Diet Money को 10

रूपये से बढ़ाकर 50 रूपये करने की घोषणा करता हूँ।

भर्त्तियां

208. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा महाविद्यालयों/विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1000 कर्मियों को नियमित किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2025–2026 के दौरान राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सुधार के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, ए.एन.एम. के 82, जे.ओ.ए.(आई0टी0) के 42 पदों को भरा जाएगा। पुलिस विभाग में पुलिस कॉंस्टेबलों के 1 हज़ार 226 पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है तथा बचे हुए 1 हज़ार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025–2026 में आरम्भ कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से सम्बन्धित बी0–1 परीक्षा लगभग 500 पदों हेतु करवाई जाएगी, इससे सम्बन्धित अधिसूचना शीध्र ही जारी कर दी जाएगी। उक्त परीक्षा को वर्ष 2017 के बाद से अभी तक नही करवाया गया है। सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राईवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कुशल एवं सुचारू संचालन के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से, तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएगें तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के 65 व सहायक अभियन्ताओं के 5 पद पदोन्नति से भरा जाएगा। जलशक्ति विभाग में 4 हज़ार 500 पैरा कर्मचारियों जिनमें 2500 मल्टीपर्पस वर्कर, 1276 पैरा पम्प ऑपरेटर, 500 पैरा फिटर, 92 पैरा कुक और 132 पैरा हैल्पर शामिल है, की नियुक्ति स्वीकृति प्रदान की गई है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

हमारी सरकार 2025–2026 के दौरान उपर्युक्त पदों सहित लगभग 25 हज़ार लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

विधायक प्राथमिकताएं

209. प्रत्येक वर्ष की भाँति माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- विधायक प्राथमिकता योजनाओं के अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे–बोर्डिंग स्कूलों को भी सम्मिलित कर पाएंगे। यदि किसी पुरानी प्राथमिकता जिसकी अभी डी0पी0आर0 न बनी हो, को भी माननीय विधायक डे–बोर्डिंग स्कूल से Substitute कर पाएंगे।

- मैं विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

कर्मचारी कल्याण

210. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह मानती है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीड की हड्डी है। पेंशनर्ज ने भी सेवाकाल के दौरान प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। परन्तु जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं पेन्शन आदि के लगभग 10 हजार करोड़ रूपये की एरियर की देनदारियां लंबित रखी थी।

211. मैं घोषणा करता हूँ कि प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। 15 मई से इस भुगतान की शुरूआत की जाएगी। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारीयों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 1 लाख 75 हज़ार से अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लाभ होगा।

वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ खर्च किये जाएंगे।

212. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किश्त 15 मई, 2025 से दी जाएगी।

213. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं, निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।
- आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा।

मानदेय वृद्धि

214. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँः–

- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 10,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 7,300 रुपये मिलेंगे।
- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 5,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 5,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 500 रुपये बढ़ाया जाएगा।

- मिड डे मील वर्कर्ज़ को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,600 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,600 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 8,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- राजस्व लम्बरदार का 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- IT Teachers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- SPOs को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

बजट अनुमान

215. अध्यक्ष महोदय, अब, मैं 2024–25 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 43 हज़ार 704 करोड़ रुपये हैं। 2024–25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 50 हज़ार 190 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2024–25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6 हज़ार 486 करोड़ रुपये का राजस्व Deficit अनुमानित हैं।

216. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025–26 के लिए 58 हज़ार 514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

217. वर्ष 2025–26 में राजस्व प्राप्तियाँ 42 हज़ार 343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48 हज़ार 733 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6 हज़ार 390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10 हज़ार 338 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत् है।

218. 2025–26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 25 रुपये, पैंशन पर 20 रुपये, ब्याज अदायगी पर 12 रुपये, ऋण अदायगी पर 10 रूपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 09 रुपये, जबकि शेष 24 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

219. अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु **अनुबन्ध** में दर्शाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द – जय हिमाचल

बजट सांराश

बजट के मुख्य बिन्दु

- ❖ 58 हज़ार 514 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।
- ❖ 2024–25 के दौरानः–
  - ➢ प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत्।
  - ➢ प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 57 हज़ार 212 रुपये अनुमानित।
  - ➢ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 32 हज़ार 185 करोड़ रुपये अनुमानित।

- ❖ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन व सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार।
- ❖ पर्यटन से विकास की ओर अग्रसर हिमाचल।
- ❖ समाज के सभी वर्गो का उत्थान एवं कल्याण।
- ❖ स्वरोजगार के क्षेत्र में नए कदम
- ❖ हरित ऊर्जा, हरित हस्तक्षेप, हरित हिमाचल, व स्वच्छ हिमाचल
- ❖ स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण व शिक्षा का रूपान्तरण
- ❖ नशामुक्त हिमाचल
- ❖ स्वच्छ पेयजल एवं सीवरेज सुविधाओं के क्षेत्र में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण
- ❖ परिवहन, उद्योग, पुल व सड़कें
- ❖ ग्रमीण विकास, पंचायती राज व शहरी विकास के क्षेत्र में कार्य
- ❖ राजस्व, आपदा व दमकल
- ❖ भर्त्तियां
- ❖ कर्मचारी कल्याण
- ❖ मानदेय
- ❖ अन्य

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन व सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार।

- ✓ जिला सोलन के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील करना।
- ✓ Wool Federation के माध्यम से ऊन के सही रख–रखाव हेतु 450 वर्ग मीटर आकार के स्टोर का निर्माण।
- ✓ घुमन्तू भेड़ बकरी पालकों के Migratory Routes को Map करके GPS से Track किया जाएगा।
- ✓ दूध Procurement का कार्य कर रही पंजीकृत Societies को मिलने वाली Freight Subsidy को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 3 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।
- ✓ Milkfed में दूध Procurement के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। साथ ही सभी पशुओं को भी Life Cycle Approach के अन्तर्गत एक Integrated Digital Platform पर लाया जाएगा।
- ✓ Dairy Development योजना के तहत Milk Processing Plant डगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना।
- ✓ नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहडू में 20 हज़ार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयन्त्र और ऊना और हमीरपुर में 2 Milk Chilling Centre (MCC) की स्थापना करना।
- ✓ गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करना।
- ✓ किसी किसान या Society द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर दूध स्वयं ले जाने पर उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से Transport Subsidy देना।
- ✓ प्रदेश के किसानों के हित में सरकार "Agriculture Loan Interest Subvention Scheme" लाएगी।

- ✓ एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य।
- ✓ किसानों को "Certified Evaluation Tool For Agriculture Resource Analysis" (CETARA Portal) पोर्टल पर Register किया जाएगा।
- ✓ प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए 40 रूपये और गेहूँ 60 रूपये प्रति किलो ग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाएगा। यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर स्वयं ले कर आते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से Freight Subsidy दी जाएगी।
- ✓ किसानों को बेहतर Marketing के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु e-Commerce Platforms, NCDC से जोड़ना।
- ✓ जिला हमीरपुर में स्पाईस पार्क (Spice Park) का निर्माण।
- ✓ प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए 90 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।
- ✓ कृषि विभाग के सभी Government Farms (सरकारी खेतों) को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा। पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगें।
- ✓ ऊना जिले में Potato Processing Plant को स्थापित करना।
- ✓ खरीफ़ 2025 से आठ Potato Development Stations में आलू के बीज का उत्पादन की शुरूआत।
- ✓ राज्य में अनाज Silos की स्थापना।
- ✓ "हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना" के अन्तर्गत 100 गाँवों में सिंचाई योजनाओं का निर्माण करके उन्हें Local Committees को Transfer, कृषि बाड़बंदी व कृषि यन्त्रीकरण में सहायता प्रदान, किसानों के लिए लगभग 1 हज़ार 500 प्रशिक्षण शिविर, 4 हज़ार Demonstrations on Vegetable

Cultivation व Millets पर लगभग 2 हज़ार 400 Demonstrations आयोजित करना।

- ✓ "मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना" को आगे बढ़ाते हुए अब Solar Fencing, जाली धार और कान्टेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान।
- ✓ 4 हज़ार हैक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए Topographic Survey किया जाएगा।
- ✓ किसान उद्यम नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
- ✓ प्रगति पर 114 Lift Irrigation Schemes वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी की जाएगी।
- ✓ HPSHIVA परियोजना के तहत 100 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।
- ✓ Weather based Crop Insurance Scheme के अन्तर्गत अब तीन और फल फसलों लीची, अनार तथा अमरूद को भी शामिल करना।
- ✓ Sub tropical बागवानी को बढ़ावा देने के लिए Sub tropical फलों के High Density Plantation के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- ✓ जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों की Royalty की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत करना।
- ✓ मुख्यमन्त्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 20 हैक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण।
- ✓ 120 नई ट्राऊट इकाइयों का निर्माण।
- ✓ पतलीकूहल में एक ट्राऊट फिश ब्रूड बैंक की स्थापना।

- ✓ मछुआरों को पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

- ✓ मछुआरों को Fish Transportation हेतु तिपहिया वाहन व मोटर साईकल का वितरण।

- ✓ 10 बायोफ्लॉक कल्चर इकाईयां, 03 ट्राऊट हेचरी, 04 मछली फीड मिल, 02 आईस प्लांट, 05 बायोफ्लॉक मछली तालाब और 02 सजावटी मछली पालन इकाईयों का निर्माण किया जाएगा।

2. पर्यटन से विकास की ओर अग्रसर हिमाचल।

- ✓ गगल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू–अधिग्रहण का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा।

- ✓ New Tourism Destinations के अन्तर्गत मनाली, कुल्लू, नग्गर व नादौन में वैलनेस सेन्टर, धर्मशाला, शिमला व मण्डी में आईस स्केटिंग रिंक, पालमपुर और नगरोटा बगवां का सौन्दर्यीकरण, बाबा बालकनाथ मन्दिर के परिसर में पर्यटन सुविधाएं व नादौन में रॉफ्टिंग सेन्टर।

- ✓ पर्यटकों की सुविधा एवं युवाओं को रोज़गार हेतु Food Vans की खरीद के लिए उपदान देना।

- ✓ Home Stay Units के लिए एक नई योजना "मुख्यमन्त्री पर्यटन स्टार्ट–अप योजना" शुरू करने की जाएगी।

- ✓ एक नई योजना के तहत 200, 3 Star या उससे उपर 7 Star तक के होटल स्थापित करने के लिए निजि क्षेत्र को निवेश के लिए आमन्त्रित करेंगे।

- ✓ माता श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर, माता श्री ज्वालाजी मन्दिर, श्री माता श्री नैना देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण तथा धर्मशाला के तपोवन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के Convention Centre का निर्माण।

- ✓ मण्डी में शिवधाम की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना।
- ✓ कांगड़ा जिले में पौंग डैम के साथ–साथ निकटतम क्षेत्रों के विकास हेतु नगरोटा सूरियां, खब्बल व Wellness Centre देहरा, काज़ा और रकछम व छितकुल को पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करना।
- ✓ बनखण्डी, कांगड़ा में Zoological Park में "Planetarium" स्थापित किया जाएगा।
- ✓ स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रदेश में चार नए Five Star स्तर के "Natural Care Wellness Centre" खोलना।
- ✓ सरकार द्वारा रक्कड़, पालमपुर, सुल्तानपुर, जसकोट और शारबो(किन्नौर) में हैलीपोर्टस का निर्माण और संचालन करना।
- ✓ सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल की तर्ज़ पर प्रदेश के चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ना।
- ✓ नई हिमाचल प्रदेश Eco-Tourism नीति–**2024** के अनुसार प्रदेश में Eco-Tourism गतिविधियों को गति देना।
- ✓ वन विभाग के विभिन्न सर्कल में भी Eco-Tourism Societies गठित की गई हैं।
- ✓ Eco-Tourism की दिशा में **78** Eco-Tourism साईटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- ✓ विभिन्न Eco-Tourism गतिविधियों के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रूपये अर्जित करने का लक्ष्य।
- ✓ पायलट आधार पर पपरोला और शिमला के आयुष अस्पतालों में पर्यटकों और आम जनता के लिए वैलनेस पंचकर्मा शुरू किया जाएगा।
- ✓ विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में पुलिस स्टेशनों/डैस्क को स्थापित करके इन्हे सम्बन्धित थानों के साथ एकीकृत किया जाना।

- ✓ कुल्लू के नग्गर में अन्तर्राष्ट्रीय रौरिक मेमोरियल ट्रस्ट के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

3. समाज के सभी वर्गों का उत्थान एवं कल्याण।

- ✓ 2025–2026 के दौरान सामाजिक पैन्शन योजनाओं में 37 हज़ार नए लाभार्थियों को शामिल करना।

- ✓ सरकारी कर्मचारी/पैन्शनभोगियों और आयकर दाता दिव्यांगजनों को छोड़कर सभी विशेष योग्यजन व्यक्तियों(दिव्यांगजन) जिनकी बैंचमार्क विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक है उनको सामाजिक सुरक्षा पैन्शन योजना (SSP) देना।

- ✓ सामाजिक सुरक्षा पैन्शन (SSP) के वितरण में पारदर्शिता और इसे प्रभावी बनाने के लिए एक End-to-End एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल/प्लेटफार्म लान्च करना।

- ✓ "इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना" में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली हर बेटी को शामिल करना। महिलाएं जो Domestic Helper के रूप में कार्य कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना से 1 जून 2025 से लाभान्वित किया जाएगा।

- ✓ Institution for Children with Special Abilities (ICSA) ढली को कर्मचारियों सहित सरकार के अधीन करना।

- ✓ सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (SJAY) के तहत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाना।

- ✓ अन्तर्जातीय विवाह के लिए मिलने वाले मौद्रिक पुरस्कार को 50 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये करना।

- ✓ "विकलांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन" नामक उप योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले

दिव्यांगजनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख करना।

- ✓ "मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना" के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करना।
- ✓ "वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम/वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करना।
- ✓ हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से स्वरोज़गार और विभिन्न लघु उद्यमों आदि के लिए कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय को बढ़ाकर 50 हज़ार रूपये करना।
- ✓ राज्य में 3 और नशा रोकथाम एवं नशामुक्ति–सह–पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित।
- ✓ बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के लिए ''इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना''।
- ✓ काम–काजी महिलाओं की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य सोलन, नीरी, दरुही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चनौर इंडस्ट्रियल एरिया और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 Working Womens' Hostels का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।
- ✓ 1 अप्रैल 2025 से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को ''आंगनवाड़ी सह प्रीस्कूल'' के रूप में नामित कर इन्हें नजदीकी स्कूलों में यथासंभव Co-locate करना।
- ✓ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य हेतु एक नई योजना ''इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना'' को लागू करना।

- ✓ नीति आयोग के साथ मिलकर जिला ऊना में पायलट आधार पर चलाए जाने वाले विंगस प्रोजक्ट (World-leading Innovative Study Programme) को पूरा करना।

4. स्वरोजगार के क्षेत्र में नए कदम

- ✓ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के छोटे फल–सब्जी विक्रेताओं, चाय दुकानदारों और अन्य के लिए "मुख्यमन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना" लाने जा रही है।

- ✓ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट–अप योजना के तहत पात्र आवेदकों को ई–टैक्सी खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा जाएगा।

- ✓ तीन हज़ार डीजल/पैट्रोल Taxi वाहनों को इलैक्ट्रिक Taxi वाहनों (e-Taxi) में परिवर्तित करने पर e-Vehicles के लिए 40 प्रतिशत तक की Subsidy प्रदान की जाएगी।

- ✓ एक हज़ार बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित किए जाएंगे । इन रूटों पर बस अथवा टैम्पों ट्रैवलर की खरीद पर Subsidy/VGF प्रदान की जाएगी।

- ✓ नए स्थानों पर हिम–ईरा शॉप्स, हिमाचली हाट तथा साथ ही Wayside Amenities का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। Wayside Amenities Scheme के प्रथम चरण में योजना राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे लागू की जाएगी।

- ✓ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन दी जाएंगी।

- ✓ National Rural Livelihoods Mission (NRLM) के अन्तर्गत 4 हज़ार योग्य अभ्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इन में से 70 प्रतिशत को सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।

- ✓ Bantony Castle शिमला के परिसर में दिल्ली हाट की तर्ज़ पर हि0प्र0 राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/शिल्पकारों हेतु स्टॉल स्थापित किए।

- ✓ राज्य की संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने हेतु दिल्ली हाट में "हिम उत्सव " का आयोजन किया जाएगा।

- ✓ जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, तीसा और अन्य चिन्हित स्थानों पर निजी क्षेत्र में 250 किलोवॉट से एक मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए 3–5 प्रतिशत का ब्याज उपदान प्रदान करेगी।

5. हरित ऊर्जा, हरित हस्तक्षेप, हरित हिमाचल, व स्वच्छ हिमाचल

- ✓ कांगड़ा के डमटाल में 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाना।

- ✓ "ग्रीन पंचायत योजना" के तहत 100 पंचायतों में 500–500 किलोवॉट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।

- ✓ शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना(450 मेगावाट) को दिसम्बर, 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है।

- ✓ एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना के कार्य को जून, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।

- ✓ पम्प भण्डारण परियोजनाओं से बिजली क्षेत्र के विकास की गति में वृद्धि।

- ✓ निजी निवेश को उर्जा क्षेत्र मे बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के उपक्रमों को निवेश का आमन्त्रण।

- ✓ कांगू (जिला मण्डी) और टहलीवाल (जिला ऊना) में 220 केवी सब–स्टेशन के कार्य की शुरूआत।

- ✓ धर्मपुर (जिला मण्डी) और बरसैनी (जिला कुल्लू) में 132 केवी के दो सब–स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

- ✓ गनोग(नूरपुर), करला कोटला(देहरा), मझीण(ज्वालामुखी), मोकी(इन्दौरा), समलोटी (नगरोटा बगवां) और थेर(ज्वालामुखी) में

आगामी वित्त वर्ष के दौरान 33KVA/11KVA के 6 Sub Station की स्थापना की जाएगी।

- ✓ 80 पेट्रोल पम्पों पर ई–वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू करने के साथ–साथ ग्रीन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर PPP मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना।

- ✓ 500 और e-Buses खरीदी जाएंगी।

- ✓ 100 जलवायु–संवेदनशील गावों की पहचान कर Climate-Smart Agriculture, और Renewable Energy Microgrids के माध्यम से विकास करने हेतु Climate Resilient Villages (CRV) Programme की शुरूआत।

- ✓ चम्बा जिले में चार सरकारी संस्थानों और शिमला जिले में दो सरकारी संस्थानों में Dome Theater स्थापना।

- ✓ प्लास्टिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "Plastic Neutral Himachal" अभियान की शुरूआत।

- ✓ Biodiversity Conservation and Protection में युवाओं की भागीदारी के लिए एक Biodiversity Guardianship Programme की शुरूआत।

- ✓ जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में समस्त पारम्पारिक ईन्धन वाले वाहनों के स्थान पर ई-वाहनों को परिवर्तित करने की शुरूआत करेगी।

- ✓ मनरेगा के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए एक Standard Operating Procedure (SoP) लागू किया जाएगा।

- ✓ वन क्षेत्र के विस्तारीकण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 5 हज़ार हैक्टेयर भूमि पर का वृक्षारोपण का लक्ष्य तय करना।

- ✓ वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ व्यय के साथ नई "राजीव गाँधी वन संवर्द्धन योजना", लागू करना।

- ✓ Corporate Social Responsibility(CSR) के अन्तर्गत एक नई Adoption योजना लाकर बंजर भूमि पर वृक्ष लगाना।

- ✓ World Bank, KFW और JICA की सहायता से वन क्षेत्र में चल रही तीन परियोजनाओं के तहत अगले वर्ष के दौरान लगभग 200 करोड़ रूपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव।

- ✓ कृषि–वानिकी फसल अवशेषों को मूल्यवान कार्बन उत्पादों में परिवर्तित करके आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के अवसर में बदलने का प्रस्ताव।

6. स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण व शिक्षा का रूपान्तरण।

- ✓ 69 संस्थानों में डॉयलेसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

- ✓ 11 संस्थानों घवांडल, चवाड़ी, भोरंज, नादौन, तयारा, जयसिंहपुर, पधर, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली व अम्ब में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना।

- ✓ हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिलों में 17 Newborn Stabilization Units स्थापित करना।

- ✓ AIMSS, Chamiana, Shimla व टॉण्डा मैडिकल कॉलेज, कांगड़ा में Robotic Surgery की स्थापना।

- ✓ IGMC Shimla में Positron Emission Tomography (PET) Scan की सुविधा की उपलब्ध करवाना।

- ✓ IGMC Shimla, AIMSS Chamiana, Shimla, Govt. Medical College Hamirpur तथा Govt Medical College Ner Chowk में अत्याधुनिक MRIs मशीनें की स्थापना।

- ✓ राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज मण्डी में कैथेटराइजेशन लैब (Cath. Lab.) की स्थापना करना।
- ✓ निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 नए Health and Wellness Centres की स्थापना करना।
- ✓ "रोगी मित्र योजना" के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक हज़ार के करीब रोगी मित्र नियुक्ति व इन्हें 15 हज़ार मासिक मानदेय प्रदान करना।
- ✓ सुगम स्वास्थ्य नाम की नई App को लॉन्च करना।
- ✓ मुफ्त इन्सुलिन पम्प उपलब्ध अब 27 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- ✓ गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 12 हज़ार रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- ✓ मुख्यमन्त्री वृद्धजन देखभाल योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टॉफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ✓ प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 25 Advanced Life Support एम्बुलेंस की खरीद करना।
- ✓ जिला काँगड़ा में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू।
- ✓ "आचार्य चरक योजना" की शुरूआत की जाएगी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों को निःशुल्क जाँच और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- ✓ प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की Digital Attendance शुरू की जाएगी।

- ✓ Government Senior Secondary Schools गगरेट, अम्ब, हरोली, बंगाणा, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इन्दौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, ढलियारा, शिलाई, रिकांगपिओ (किन्नौर), केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिन्द्रनगर को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

- ✓ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन किया जाएगा।

- ✓ सुजानपुर स्थित सैनिक स्कूल को Hostel की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

- ✓ कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए 4 Hostel बनाए जाएंगे। साथ ही हमीरपुर और सुजानपुर में स्कूली लड़कियों के लिए Hostel बनाए जाएंगें।

- ✓ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक विचारों और पहलों को शुरु करने के लिए Innovation Fund की स्थापना।

- ✓ राजकीय हाईड्रो इन्जीनियरिंग महाविद्यालय बान्दला में एम.टैक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Vehicle Technology) की कक्षाएं चलाई जाएगी।

- ✓ जिला बिलासपुर के घुमारवीं में Digital University of Innovation, Entrepreneurship, Skill, and Vocational Studies की स्थापना सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP Mode) व Self Financing पर की जाएगी।

7. नशामुक्त हिमाचल।

- ✓ नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Drug Dependence Prevention, De-addiction, and Rehabilitation Board का गठन करना।

- ✓ मैडिकल कॉलेज, टाण्डा में एक Drug-De-addiction and Rehabilitation नोडल केन्द्र स्थापित करना।

- ✓ सिरमौर जिले में एक Drug-De-addiction and Rehabilitation केंद्र चालू किया जाएगा।

- ✓ क्षेत्रीय/जिला/मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार डि–एडिक्शन बैडस की संख्या में बढ़ोतरी करना।

- ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के डॉक्टर और पैरामैडिकल स्टॉफ द्वारा नजदीकी स्कूलों में छात्रों की स्वास्थ्य जांच व Counselling-cum-Awareness Session हेतु "स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम" की शुरूआत।

- ✓ HP Anti Drug Act के प्रावधानों के माध्यम से नशे से जूझ रहे लोगों के लिए Punitive Measures के स्थान पर पुर्नवास पर जोर।

- ✓ नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए Special Task Force (STF) बनाने की घोषणा।

- ✓ संगठित अपराध सिण्डिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए "Himachal Pradesh Prevention of Continuing Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act, 2025" लाया जाना।

४. स्वच्छ पेयजल एवं सीवरेज सुविधाओं के क्षेत्र में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण।

- ✓ जिला लाहौल स्पिति के लिए 27 करोड़ रूपये की लागत से 20 Water Supply Schemes और किन्नौर जिले में 72 करोड़ रूपये की लागत से 6 Water Supply Schemes का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

- ✓ नादौन, भोरन्ज, अमलेहड़ और हरोली में 4 Water Supply Schemes और बद्दी के लिए एक Sewerage Scheme का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

- ✓ भुन्तर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निरमण्ड, जोगिन्द्रनगर, शाहपुर, भटियात और करसोग नगरों में कुल 167 करोड़ रूपये की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा।

- ✓ कुल 12 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 पेयजल आपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत 5 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है तथा शेष क्षेत्रों में शीघ्र की कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

- ✓ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन परियोजना के तहत 7 सौ 45 करोड़ की लागत से 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हज़ार 663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

- ✓ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन एवं आजीविका परियोजना के तहत Functional House Hold Tap Connection(FHTCs) का शेष 57 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाएगा।

- ✓ हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ नई मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की शुरूआत।

- ✓ जिला कांगड़ा के देहरा, ज्वाला जी, जंसवां व प्रागपुर में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 43 करोड़ रूपये की लागत से Drinking Water Treatment Plant लगाया जाएगा।

- ✓ पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 14 Bacteriological मापदण्डों लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।

- ✓ नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर और बिलासपुर नगरों के लिए सीवरेज योजनाओं का कार्य 2025–2026 में आरम्भ कर दिया जाएगा।

- ✓ कांगड़ा, मण्डी, चम्बा और किन्नौर ज़िलों के 14 कस्बों में सीवरेज योजनाओं पर कार्य 2025–2026 में शुरू किया जाएगा।

९. परिवहन, उद्योग, पुल व सड़कें

- ✓ परिवहन निगम में अतिरिक्त ५०० e–Buses की खरीद व ऑनलाईन पास सुविधा शिमला के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य स्थानों में शुरू करने हेतु Software तैयार किया जाएगा।

- ✓ शिमला शहर में 1 हज़ार ५४६ करोड़ ४० लाख रूपये की लागत से १४.७९ किलो मीटर लम्बी रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

- ✓ शिमला शहर में पायलट आधार पर Luxury Vehicles को चयनित रूटों पर चलाए जाएगें।

- ✓ ऊना जिले के हरोली में पहला Automatic Driving Test Track स्थापित किया जाएगा।

- ✓ जलमार्गों में जैटीज़ आदि का विकास और क्रूज पर्यटन, जल क्रीड़ा गतिविधियों और जल परिवहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

- ✓ बल्क ड्रग पार्क में आगामी वर्ष में कार्य को सुचारू रखने के लिए आवश्यकता अनुसार बजट का प्रावधान करना।

- ✓ प्रदेश की औद्यौगिक नीति में मूलभूत बदलाव करना। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन व इलैक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने हेतु Investor Outreach Programmes आयोजित किए जाना।

- ✓ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास।

- ✓ एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करेगा और सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करेगा।

- ✓ 66 KV या उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी दी जाएगी।

- ✓ 3 सौ 45 करोड़ 14 लाख रूपये की लागत से 6 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं के निर्माण की शुरूआत।

- ✓ NABARD के तहत 4 सौ 98 करोड़ 62 लाख रूपये की 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति।

- ✓ निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करना तथा कार्यों को Award करने का कुल समय 12 दिन करके निष्पादन में तेजी लाना।

- ✓ "मुख्यमन्त्री सड़क योजना" के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान करना।

10. ग्रामीण विकास, पंचायती राज व शहरी विकास के क्षेत्र में कार्य

- ✓ प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए हम ब्लॉकों का पुनर्गठन करेंगे।

- ✓ ग्रामीण संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए 09 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (Extension Training Centres) स्थापित किए जाएंगे।

- ✓ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पानी की योजनाओं को पंचायत स्तर पर देगें ताकि वे अपनी आय में बढ़ोहतरी कर सकें तथा आय के अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी सम्पतियां की Lease Management की जाएगी।

- ✓ 2025–2026 हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में विकास कार्य हेतु 452 करोड़ रूपये तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

- ✓ नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए प्रत्येक को एक करोड़, नगर परिषद नादौन, बैजनाथ–पपरोला और सुन्नी के लिए 25 लाख प्रत्येक तथा नवगठित 14 नगर पंचायतों के लिए 50 लाख प्रत्येक के रूप में विकासात्मक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

- ✓ नव गठित शहरी निकायों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्षों तक पानी के रेट पहले के समान ही रहेगें।

- ✓ शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रदान की जा रही लगभग 44 सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से UPYOG प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।

- ✓ वर्तमान विकास योजनाओं का पुनर्निरीक्षण तथा महत्वपूर्ण शहरी/पर्यटक क्षेत्रों में "Business District Zone" की स्थापना।

11. राजस्व, आपदा व दमकल

- ✓ सभी राजस्व न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल करना तथा प्रदेश में ई–राजस्व प्रणाली लागू करना।

- ✓ Revenue Court Management System(RMS) के अन्तर्गत एक मॉडयूल विकसित करना जो नागरिकों से सम्बन्धित भूमि रिकॉर्ड के सीमाँकन और नामान्तरण से जुड़े मामलों की मैपिंग।

- ✓ Aerial Survey Technology के माध्यम से चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक जमीनी स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड तैयार करना।

- ✓ डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से ततीमा(Maps) उपलब्ध करवाने हेतु भू–नक्शा एप्लीकेशन का उपयोग।

- ✓ ऑनलाइन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर शुरू करके म्यूटेशन की प्रक्रिया को डिजिटल करना और एक पेपरलेस प्रणाली स्थापित करना।

- ✓ आपदाओं से निपटने के लिए 3 हजार 645 पंचायतों में एक संगठित और सामुदायिक संचालित "पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र" की स्थापना।
- ✓ AFD के माध्यम से लगभग 892 करोड़ रूपये की लागत से आगामी पांच वर्षो के लिए परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैंः–
- ✓ Disaster Risk Reduction and Preparedness Project के तहत Multi Hazards के लिए Early Warning System का विकास और GIS पर आधरित Decision Support System
- ✓ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के परिसरों की स्थापना।
- ✓ भूस्खलन रोकने और ढलानों को स्थिर करने के लिए Bio-Engineering उपायों का प्रोत्साहन।
- ✓ उप–मण्डल और तहसील स्तर पर भी "Disaster Risk Reduction Co-ordination Centre" की स्थापना।
- ✓ HP State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authorities, State Emergency Operation Cell, District Emergency Operation Cells को सुदृढ़ करना।
- ✓ कृषि और बागवानी के लिए जलवायु/मौसम पूर्वानुमान का विकास।
- ✓ जंगल की आग के खतरों को कम करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा।
- ✓ जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन से सम्बन्धित अध्ययन। भूकंप–प्रतिरोधी तकनीकों को बढ़ावा देना।
- ✓ Disaster Risk Reduction के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।
- ✓ Himalayan Disaster Risk Reduction Centre की पालमपुर स्थापना।

- ✓ राजगढ़ जिला सिरमौर और कण्डाघाट जिला सोलन में दमकल केंद्र खोलना।
- ✓ नादौन, इन्दौरा, राजगढ़, और कण्डाघाट में 8 नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करना और पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदाना।

- ✓ 16 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल, प्रशिक्षण और जनसमुदाय को जागरूकता प्रदान करने हेतु 2 बसें और विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों को खरीदाना।

- ✓ उप दमकल केन्द्र काज़ा व कुमारसैन; जोगिन्द्रनगर, फतेहपुर व आनी की दमकल चौकियों के विभागीय भवनों का निर्माण।

12. भर्त्तियां

- ✓ महाविद्यालयों/विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे।
- ✓ आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, ए.एन.एम. के 82, जे.ओ.ए.(आई0टी0) के 42 पदों को भरा जाएगा।
- ✓ पुलिस विभाग में पुलिस कॉंस्टेबलों 1 हज़ार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025–2026 में आरम्भ कर दी जाएगी।
- ✓ पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से सम्बन्धित बी0–1 परीक्षा लगभग 500 पदों हेतु करवाई जाएगी।
- ✓ गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राईवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरा जाएगा।
- ✓ पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएगें।
- ✓ स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा।
- ✓ सभी श्रेणियों की 25 हजार भर्त्तियां।

13. कर्मचारी कल्याण

- ✓ 15 मई से प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारीयों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा।
- ✓ 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किश्त।
- ✓ दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।
- ✓ आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ मनरेगा मजदूरी को 20 रूपये बढ़ाकर 320 रूपये किया जाएगा।

14. मानदेय

- ✓ अध्यक्ष, जिला परिषद को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 19,000 रुपये, सदस्य, जिला परिषद को 8,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 9,000 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति को 7,500 रुपये, प्रधान, ग्राम पंचायत को 7,500 रुपये, उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य, ग्राम पंचायत को 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

- ✓ महापौर, नगर निगम को 25,000 रुपये, उप–महापौर, नगर निगम को 19,000 रुपये, काउंसलर, नगर निगम को 9,400 रुपये, अध्यक्ष, नगर परिषद को 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 8,900 रुपये, पार्षद, नगर परिषद को 4,500 रुपये, प्रधान, नगर पंचायत को 9,000 रुपये, उप–प्रधान, नगर पंचायत को 7,000 रुपये तथा सदस्य, नगर पंचायत को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- ✓ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,800 रुपये, आशा वर्कर को 5,800 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 5,000 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5,500 रुपये, जल रक्षक को 5,600 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 5,500 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 6,600 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,500 रुपये, राजस्व चौकीदार को 6,300 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500 रूपये, लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers के मासिक मानदेय को 500 रुपये प्रतिमाह, SMC अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह, IT Teachers को 500 रुपये प्रतिमाह, SPOs को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- ✓ प्रदेश के Medical Colleges/AIMSS Chamiana में PG विद्यार्थियों के लिए Senior Resident/Tutor Specialist को वर्तमान में वज़ीफे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रूपये की जाएगी तथा साथ ही DNB-Super Specialist & Sr. Residents-Super Specialist(D.M./M.Ch.) के वज़ीफे की राशि को भी बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रूपये की जाएगी।
- ✓ प्रदेश में ऑउटसोर्स पर नियुक्त Operation Theater Assistant and Radiographer, की मासिक मानदेय राशि बढ़ाकर 25 हज़ार रूपये की जाएगी।

15. अन्य

- ✓ आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें Artificial Inteligence (AI) का प्रयोग किया जाएगा।
- ✓ शिमला के मैहली और कांगडा के चैतडू में स्थापित किए जा रहे Software Technology Park(STPI) पर कार्य पूरा किया जाएगा।
- ✓ सरकार Drone Taxi सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। Drone Technology Intervention से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी

आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मण्डी और कांगड़ा में Drone Station स्थापित किए जाएंगे।

- ✓ बसाल(बिलासपुर) और बिन्द्रावन(पालमपुर) में आवासीय कलौनियां तथा रामपुर फेज–3, रजवाड़ी(मण्डी) व धर्मपुर(सोलन) में लगभग 82 फ्लैटों और 137 रिहायशी प्लाटों को विकसित किया जाएगा।
- ✓ हिमुडा द्वारा विकासनगर, शिमला में 250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक विशाल व्यवसायिक परिसर के निर्माण किया जाएगा।
- ✓ बिलासपुर के लूहणू में 100 बिस्तरों वाला खेल छात्रावास।
- ✓ जिला हमीरपुर के खरीड़ी में 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास।
- ✓ शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुद्देशीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- ✓ सोलन में इण्डोर स्टेडियम के साथ–साथ रिंकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ हमीरपुर तथा सुजानपुर में Synthetic Track and Field सुविधा का निर्माण।
- ✓ विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता से भर्ती।
- ✓ Sainik School में पढ़ रहे बच्चों को दी जाने वाली Diet Money को 10 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपये करने की घोषणा।
- ✓ हम Climate Change को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक दूरगामी नीति बनाई जाएगी।
- ✓ सरकार द्वारा राज्य के छोटे मन्दिरों को वर्तमान में दी जा रही अनुदान की राशि को दोगुना करना।
- ✓ विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे–बोर्डिंग स्कूलों को भी सम्मिलित कर पाएंगे।
- ✓ विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा।